GUPTA CLASSES

करेंट अफेयर्स

जनवरी-2022

हिन्दी

भाग-3

GUPTA CLASSES

टैगलाइन- अपने लिए. अपनों के लिए

WB ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन-लिंक्ड बॉन्ड पेश किया

24 जनवरी 2024 को, विश्व बैंक ने विश्व स्तर पर विश्व बैंक की सतत विकास गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 7-वर्षीय USD 100 मिलियन प्रिंसिपल-संरक्षित प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण-लिंक्ड बॉन्ड लॉन्च किया।

- बॉन्ड का ध्यान प्रकृति और महासागरों में प्लास्टिक वेस्ट के रिसाव को रोकने पर है।
- **सिटी** ने इस बॉन्ड के लिए लीड मैनेजर के रूप में कार्य किया।

बॉन्ड के बारे में:

i.इस बॉन्ड में **घाना** और **इंडोनेशिया** में दो प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन और रीसाइक्लिंग परियोजनाओं से प्लास्टिक वेस्ट रीसाइक्लिंग क्रेडिट, प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन क्रेडिट (सामूहिक रूप से प्लास्टिक क्रेडिट के रूप में जाना जाता है), और वेरिफाइड कार्बन यूनिट्स ("**VCU**") के जारी करने और मुद्रीकरण के लिए निवेशकों की वापसी को जोड़ने की एक अनूठी विशेषता है।
ii.बॉन्ड को लक्ज़मबर्ग में **लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज** में सूचीबद्ध किया जाएगा, और स्टैंडर्ड & पूअर्स द्वारा AAA रेटिंग दिए जाने की उम्मीद है।
iii.बॉन्ड निवेशकों को लगभग न्यूनतम गारंटीशुदा रिटर्न प्रदान करते हुए सममूल्य पर जारी किया गया था। 1.75%.
iv.IBRD ने किसी भी प्लास्टिक क्रेडिट या VCU एक्सपोजर से बचाव के लिए **सिटी** के साथ **फॉरवर्ड फ्लो एग्रीमेंट** (FFA) में प्रवेश किया है।

विश्व बैंक (WB) के बारे में:

अध्यक्ष (WB समूह)– अजय बंगा
स्थापना- 1944
मुख्यालय– वाशिंगटन D.C., संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
सदस्य- 189 सदस्य देश

FINANCE NEWS

बजाज फिनसर्व ने CIBIL द्वारा संचालित भारत का पहला क्रेडिट पास लॉन्च किया

बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने एक **क्रेडिट पास** लॉन्च किया है, जो भारत में अपनी तरह की पहली सदस्यता है, जो अपने ग्राहकों को क्रेडिट हेल्थ को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए अपने क्रेडिट डैशबोर्ड तक वास्तविक समय तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

- क्रेडिट पास भारत में संचालित एक क्रेडिट सूचना कंपनी **(CIC) ट्रांसयूनियन CIBIL लिमिटेड** (पूर्व में क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड) द्वारा संचालित है।

पात्रता:

कोई भी ग्राहक जिसने पहले ऋण या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है या जो भविष्य में ऋण के लिए आवेदन करना चाहता है, वह क्रेडिट पास के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।

क्रेडिट पास:

i.क्रेडिट पास खाते तक **12 अंकों** के अद्वितीय नंबर के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।
ii.पास क्रेडिट डैशबोर्ड तक पहुंच प्रदान करता है जो क्रेडिट पूछताछ & पुनर्भुगतान इतिहास जैसी जानकारी देता है।
iii.क्रेडिट पास क्रेडिट स्कोर सिम्युलेटर और समान मासिक किस्त (EMI) कैलकुलेटर जैसे इंटरैक्टिव टूल के साथ आता है।
iv.मासिक CIBIL स्कोर चेक्स, क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट और ट्रैकिंग क्रेडिट कारक क्रेडिट पास की कुछ विशेषताएं हैं।

CIBIL स्कोर क्या है?

i.2007 में शुरू किया गया CIBIL स्कोर बैंकों और फाइनेंसियल संस्थानों के लिए भारत का पहला जेनेरिक रिस्क स्कोरिंग मॉडल था।

ii.CIBIL स्कोर **300-900** के बीच एक तीन अंकों की संख्या है, 300 सबसे कम है, जो किसी व्यक्ति की क्रेडिट-योग्यता को दर्शाता है।

iii.उच्च CIBIL स्कोर एक अच्छे क्रेडिट इतिहास और जिम्मेदार पुनर्भुगतान व्यवहार का सुझाव देता है।

बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने 8.85% की ब्याज दर के साथ डिजिटल FD की घोषणा की

एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (**NBFC**), और बजाज फिनसर्व लिमिटेड की सहायक कंपनी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड **(BFL)** ने डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट **(FD)** लॉन्च किया है जो **8.85%** तक की ब्याज दरें प्रदान करता है।

FD के बारे में:

i.डिजिटल FD को बजाज फिनसर्व मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइट के माध्यम से बुक किया जा सकता है।

ii.संशोधित दरें 42 महीने (3.5 वर्ष) की अवधि के लिए 5 करोड़ रुपये तक की नई डिपॉजिट और परिपक्व डिपॉजिट के नवीनीकरण पर लागू होंगी।

iii.वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) को 8.85% ब्याज दरों की पेशकश की जाएगी जबकि अन्य डेपोसिटर्स (60 वर्ष से कम) को 8.6% की ब्याज दरों का भुगतान किया जाएगा।

अतिरिक्त जानकारी:

वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित और अधिकृत 4 CIC हैं। वे हैं,

i.ट्रांसयूनियन CIBIL लिमिटेड

ii.इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,

iii.एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और

iv.CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

बजाज फिनसर्व लिमिटेड के बारे में:

बजाज फिनसर्व लिमिटेड बजाज समूह की फाइनेंसियल शाखा है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) – संजीव बजाज

मुख्यालय – पुणे, महाराष्ट्र

स्थापित - 2007

मैक्स लाइफ ने ULIP सेगमेंट में अपनी तरह का पहला मिडकैप मोमेंटम इंडेक्स फंड लॉन्च किया

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (**ULIP**) सेगमेंट में अपनी तरह का पहला **मिडकैप मोमेंटम इंडेक्स फंड** पेश किया है।

- न्यू फंड ऑफरिंग **(NFO)** का लक्ष्य **NSE मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स** के घटकों से निकाले गए शेयरों की एक टोकरी में निवेश करना है।

मिडकैप मोमेंटम इंडेक्स फंड के बारे में:

i.NFO उन शेयरों में निवेश करेगा, जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (FY20-FY23) में प्रबंधन के तहत संपत्ति **(AUM)** में 175% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर **(CAGR)** देखी है।

ii.NFO **मिड-कैप** कंपनियों की वृद्धि क्षमता को लक्षित करता है।

iii.फंड सिद्ध, उच्च प्रदर्शन वाले मिडकैप शेयरों में निवेश करके, फंड प्रबंधकों पर निर्भरता को कम करके व्यापक विविधीकरण लाभ प्रदान करता है।

iv.लॉन्च अवधि के दौरान, फंड मैक्स लाइफ ऑनलाइन सेविंग्स प्लान के साथ शून्य आवंटन और व्यवस्थापक शुल्क के साथ उपलब्ध है।

- इसे मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर और कैपिटल गारंटी सोलुशन के साथ भी पेश किया जाता है जो मार्केट-लिंक्ड के रूप में OSP की पेशकश करते हैं।

v.निवेशक 29 जनवरी 2024 तक NFO में भाग ले सकते हैं।

NFO क्या है?

i.NFO किसी निवेश कंपनी द्वारा लॉन्च किए जा रहे किसी भी फंड के लिए पहली सदस्यता पेशकश है।

ii.NFO के दौरान, निवेशक अंकित मूल्य पर म्यूचुअल फंड योजना की यूनिट खरीद सकते हैं, जो आम तौर पर 10 रुपये प्रति यूनिट की निश्चित कीमत पर निर्धारित होती है।

मिड-कैप:

i.भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के मामले में 101 से 250 तक रैंक वाली कंपनियों को मिड-कैप कंपनियों के रूप में जाना जाता है।

- म्यूचुअल फंड जो मिड-कैप से स्टॉक रखते हैं उन्हें '**मिड-कैप फंड**' कहा जाता है।

ii.मिड-कैप फंड में लार्ज-कैप फंड की तुलना में अधिक जोखिम होता है, लेकिन लंबे समय में ये अच्छा रिटर्न देंगे।

iii.मिड-कैप स्टॉक उच्च जोखिम और कम जोखिम दोनों निवेश रणनीतियों के पूरक हो सकते हैं, जो निवेशकों को स्थिरता और वृद्धि का संतुलन प्रदान करते हैं।

नोट- ULIP निवेश और जीवन बीमा का दोहरा लाभ प्रदान करते हैं।

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में:

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक्सिस बैंक लिमिटेड (30% हिस्सेदारी रखने वाली) और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (70% हिस्सेदारी रखने वाली) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

प्रबंध निदेशक (MD) & मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) - प्रशांत त्रिपाठी

मुख्यालय-गुरुग्राम, हरियाणा

स्थापित – 2000

IRDAI ने बीमा कंपनियों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के नियमों को आसान बनाया

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (**IRDAI**) ने बीमा कंपनियों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कम्पनीज (**IDF – NBFC**) में निवेश के लिए केस-टू-केस अनुमोदन की आवश्यकता को हटा दिया है।

- इस कदम का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है।
- यह अगस्त 2023 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक **(RBI)** द्वारा प्रदान किए गए IDF-NBFC के लिए अद्यतन नियमों के अनुरूप है।

मानदंड:

IDF-NBFC में बीमाकर्ताओं का निवेश निम्नलिखित मानदंडों के अधीन है:

i.IDF-NBFC को RBI के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

ii.निवेश के लिए पात्र होने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**SEBI**) के साथ पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (**CRA**) द्वारा AA या इसके समकक्ष न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग है।

iii.इन ऋण प्रतिभूतियों का शेष कार्यकाल कम से कम पांच वर्ष का होगा।

iv.निवेश IRDAI (निवेश) विनियम 2016 के विनियम 9 के नोट 3 के अनुरूप होना चाहिए।

नोट: केस-टू-केस अनुमोदन की आवश्यकता IRDAI (निवेश) विनियम 2016 के विनियमन 9 के नोट 2 द्वारा निर्धारित की गई थी।

IDF-NBFC क्या है?

i.एक IDF या तो एक ट्रस्ट या एक कंपनी के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

- यदि एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जाता है, तो इसे IDF-म्यूचुअल फंड (IDF-MF) के रूप में नामित किया जाता है और SEBI द्वारा विनियमित किया जाता है।
- यदि एक कंपनी के रूप में स्थापित किया जाता है, तो इसे IDF-NBFC के रूप में लेबल किया जाता है और यह RBI द्वारा विनियमन के अधीन है।

ii.IDF-NBFC का मतलब जमा न लेने वाली NBFC है जो निम्नलिखित के लिए अधिकृत है:

- परिचालन प्रारंभ तिथि (**COD**) के बाद पुनर्वित्त उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पुनर्वित्त करें, जिन्होंने संतोषजनक वाणिज्यिक संचालन का कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया है।
- वे प्रत्यक्ष ऋणदाता के रूप में टोल ऑपरेट ट्रांसफर (TOT) प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के बारे में:

अध्यक्ष – देबाशीष पांडा

मुख्यालय - हैदराबाद, तेलंगाना

स्थापित - 1999 (लेकिन 2000 में निगमित)

ज़ेरोधा फंड हाउस ने भारत की पहली ग्रोथ लिक्विड ETF योजना लॉन्च की, जिसका नाम 'ज़ेरोधा निफ्टी 1D रेट लिक्विड ETF' है

ज़ेरोधा फंड हाउस ने भारत के पहले ग्रोथ लिक्विड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) - ज़ेरोधा निफ्टी 1D रेट लिक्विड ETF के लॉन्च की घोषणा की, जो ग्रोथ नेट एसेट वैल्यू (NAV) प्रदान करता है।

ज़ेरोधा निफ्टी 1D रेट लिक्विड ETF के बारे में:

i.नई योजना **निफ्टी 1D रेट इंडेक्स** का अनुसरण करती है, जो अपने बेंचमार्क के रूप में रातोंरात बाजार में उधार देने वाले बाजार प्रतिभागियों द्वारा उत्पन्न रिटर्न को मापता है।

ii.यह योजना अपेक्षाकृत कम जोखिम वाली प्रोफ़ाइल को बनाए रखते हुए तरलता को प्राथमिकता देने के लिए डिज़ाइन की गई है।

iii.फंड के **24 जनवरी 2024** तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।

नोट: यह प्रभावी ढंग से पार्किंग और अतिरिक्त नकदी के प्रबंधन के लिए एक सरल ETF है। न्यू फंड ऑफर (NFO) 12 जनवरी 2024 तक सार्वजनिक सदस्यता के लिए खुला है।

उद्देश्य: ट्रैकिंग त्रुटियों, शुल्क और खर्चों के अधीन, खर्चों से पहले निफ्टी 50 कुल रिटर्न इंडेक्स द्वारा दर्शाए गए प्रतिभूतियों के कुल रिटर्न को प्रतिबिंबित करना।

प्रमुख बिंदु:

i.यह योजना सरकारी प्रतिभूतियों पर त्रि-पक्ष रेपो या ट्रेजरी बिल पुनर्खरीद (TREPS), T-बिल, रिवर्स रेपो, नकद और नकद समकक्ष, और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाले G-सेक (s) जैसे रातोंरात साधनों में निवेश करती है।

ii.अन्य ETF के विपरीत, जो लाभांश भुगतान के कारण निरंतर कराधान का सामना करते हैं, ज़ेरोधा निफ्टी 1D रेट लिक्विड ETF पर केवल तभी कर लगता है जब ETF बेचा जाता है।

फ़ायदे:

i.यह ETF उन निवेशकों/व्यापारियों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प साबित होता है जिनके पास अधिशेष फंड है जो कम अवधि में तरलता और विकास दोनों चाहते हैं।

ii.यह अपेक्षाकृत कम ब्याज दर और क्रेडिट जोखिम के साथ नकदी प्रबंधन का एक सरल और प्रभावी तरीका प्रदान करता है।
iii.निवेशक अपने पसंदीदा स्टॉक ब्रोकरों के माध्यम से जेरोधा निफ्टी 1D रेट लिक्विड ETF में अपना निवेश शुरू कर सकते हैं।
iv.निवेशक इस योजना के तहत प्रति प्लान/विकल्प 500 रुपये की न्यूनतम आवेदन राशि और 1 रुपये के गुणकों में निवेश कर सकते हैं।

- निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

v.अधिक खुदरा निवेशकों को सक्षम करने के लिए, ETF का टिकट आकार कम होगा, जिसकी शुरुआत 100 के NAV से होगी।

जेरोधा फंड हाउस के बारे में:
ज़ेरोधा फंड हाउस, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC), ज़ेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड और स्मॉलकेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम (JV) है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) & बिक्री प्रमुख- विशाल जैन
मुख्यालय– बेंगलुरु, कर्नाटक
निगमित - 2021

नारायण हेल्थ को हेल्थ इंश्योरेंस व्यवसाय शुरू करने के लिए IRDAI की मंजूरी मिली

बेंगलुरु (कर्नाटक) स्थित नारायण हृदयालय लिमिटेड की सहायक कंपनी **नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड** (नारायण वन हेल्थ) को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) से लाइसेंस प्राप्त हुआ है।

- IRDAI की मंजूरी हेल्थकेर प्रदाता को सहायक कंपनी के माध्यम से अपने व्यवसाय को हेल्थ इंश्योरेंस व्यवसाय में विविधता लाने और एकीकृत हेल्थकेअर की पेशकश करने की अनुमति देगी।

ध्यान देने योग्य बातें:

i.IRDAI ने 28 दिसंबर 2023 को आयोजित अपनी 124वीं बैठक में 5 साल के अंतराल के बाद भारत में हेल्थ इंश्योरेंस व्यवसाय चलाने के लिए एक नए हेल्थ इंश्योरर नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया है।
ii.अनुमोदन के बाद, स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों (SAHI) की संख्या मौजूदा 5 से बढ़कर 6 हो गई।
iii.यह इंश्योरेंस व्यवसाय की किसी भी पंक्ति में कैलेंडर वर्ष 2023 में IRDAI की 5वीं मंजूरी थी।

प्रमुख बिंदु:

i.IRDAI (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के अनुसार लाइसेंस का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण किया जाएगा।
ii.नारायण हेल्थ पूरे भारत में 38 मल्टी-स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों, हृदय केंद्रों और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं का एक नेटवर्क संचालित करता है।

- पश्चिमी कैरेबियन सागर में स्थित ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र केमैन द्वीप समूह में इसका एक अंतरराष्ट्रीय अस्पताल (शामिल) भी है।

वैश्विक मान्यता:

नारायण हेल्थ संयुक्त आयोग अंतर्राष्ट्रीय (JCI) से एंटरप्राइज़ अक्रेडेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला और वैश्विक स्तर पर छठा हेल्थकेयर समूह है।

- JCI की मान्यता नारायण हेल्थ ग्रुप के 8 व्यक्तिगत अस्पतालों तक फैली हुई है।

नारायण हेल्थ के बारे में

संस्थापक और अध्यक्ष– डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी

मुख्यालय– बेंगलुरु, कर्नाटक

स्थापित- 2000

ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने लाभ बढ़ाने वाले ICICI प्रू गारंटीड पेंशन प्लान फ्लेक्सी लॉन्च किया

ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने "लाभ बढ़ाने वाला" **ICICI प्रू गारंटीड पेंशन प्लान फ्लेक्सी** नाम से एक सेवानिवृत्ति वार्षिकी प्लान शुरू की, जो पॉलिसीधारकों को खरीदारी के बाद किसी भी समय भुगतान किए गए प्रीमियम का **100% रिफंड** प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करती है, यदि वे प्रीमियम का भुगतान जारी रखने में असमर्थ हैं।

- **ICICI प्रू गारंटीड पेंशन प्लान फ्लेक्सी** इसे उद्योग की पहली वार्षिकी प्लान होने का दावा कर रही है।

फ़ायदे:

i.यह अप्रत्याशित वित्तीय दायित्वों से उबरने में पॉलिसीधारकों की सहायता के लिए ऋण सुविधा प्रदान करता है।

- यह उन्हें उत्पाद में निवेशित रहने और अपने सेवानिवृत्ति प्लानिंग गोल को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

ii.यह आस्थगित वार्षिकी प्लान पॉलिसीधारकों को सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत आजीवन आय बनाने की अनुमति देती है और विभिन्न प्रकार के वार्षिकी विकल्प भी प्रदान करती है।

प्रमुख विशेषताऐं:

i.प्रीमियम भुगतान आवृत्तियों के विकल्प वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और मासिक हो सकते हैं, जबकि प्रीमियम भुगतान अवधि (PPT) 5 से 15 वर्ष तक होती है।

ii.न्यूनतम प्रवेश आयु 40 वर्ष (प्राथमिक वार्षिकीग्राही) और 30 वर्ष (द्वितीयक वार्षिकीग्राही) है, बूस्टर विकल्प को छोड़कर, अधिकतम प्रवेश आयु 70 वर्ष निर्धारित है।

iii.आस्थगन अवधि न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 15 वर्ष के लिए होगी, जो पॉलिसी की शुरुआत से शुरू होती है।

iv.भुगतान की जाने वाली न्यूनतम वार्षिकी 12,000 रुपये प्रति वर्ष (1,000 रुपये प्रति माह) है।

वार्षिकी विकल्प:

यह योजना सेवानिवृत्ति आवश्यकताओं के अनुसार चुनने के लिए 7 विकल्प प्रदान करती है:

- प्रीमियम की वापसी के बिना एकल जीवन;
- प्रीमियम की वापसी के बिना संयुक्त जीवन;
- प्रीमियम की वापसी के साथ एकल जीवन;
- प्रीमियम की वापसी के साथ संयुक्त जीवन;
- गंभीर बीमारी (CI) या दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता (PD) या मृत्यु पर प्रीमियम की वापसी (ROP) के साथ एकल जीवन;
- बूस्टर भुगतान के साथ एकल जीवन; और
- त्वरित स्वास्थ्य बूस्टर के साथ एकल जीवन।

प्रमुख बिंदु:

i.एकल प्लान में, वार्षिकी चयनित स्थगन अवधि के बाद शुरू होती है और राशि का भुगतान वार्षिकीधारक के जीवनकाल के दौरान किया जाएगा।

ii.संयुक्त प्लान प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु के बाद द्वितीयक वार्षिकीग्राही को आय प्रदान करती है।

- द्वितीयक वार्षिकीग्राही प्राथमिक वार्षिकीग्राही का जीवनसाथी, बच्चा, माता-पिता या भाई-बहन हो सकता है।

प्रीमियम छूट सुविधा:

संयुक्त जीवन विकल्प में प्रीमियम सुविधा की छूट शामिल है। प्राथमिक वार्षिकीधारक की असामयिक मृत्यु के मामले में, भविष्य के सभी प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं, यह गारंटी देते हुए कि द्वितीयक वार्षिकीग्राही को आजीवन नियमित आय प्राप्त होती रहेगी।

ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ICICI प्रूडेंशियल लाइफ) के बारे में:

प्रबंध निदेशक (MD) & CEO– श्री अनुप बागची
मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र
निगमित – 2000
परिचालन प्रारंभ - 2001

LIC ने एक नई वार्षिकी योजना 'जीवन धारा-2 योजना 872' लॉन्च की

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने एक नई व्यक्तिगत, बचत, आस्थगित वार्षिकी (पेंशन) योजना '**जीवन धारा-2 योजना 872**' लॉन्च की है।

- यह योजना **22 जनवरी 2024** से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

जीवन धारा II के बारे में:

i.योजना पॉलिसीधारकों को 11 वार्षिकी विकल्प प्रदान करती है और योजना की शुरुआत से वार्षिकी की गारंटी दी जाती है।
ii.पॉलिसीधारक को अपने प्रीमियम का भुगतान करने के लिए '**रेगुलर प्रीमियम**' और '**सिंगल प्रीमियम**' नामक दो विकल्प मिलते हैं।

iii.पात्रता: प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 20 वर्ष (अंतिम जन्मदिन) और अधिकतम 80, 70, 65 वर्ष, आस्थगन अवधि घटाकर है।
iv.आस्थगन अवधि: रेगुलर प्रीमियम के मामले में उपलब्ध आस्थगन अवधि 5 वर्ष से 15 वर्ष तक है और सिंगल प्रीमियम के लिए 1 वर्ष से 15 वर्ष तक है।
v.यह योजना दो विकल्पों अर्थात् 'एकल जीवन वार्षिकी' और 'संयुक्त जीवन वार्षिकी' में वार्षिकी प्रदान करती है। यह योजना अधिक उम्र में उच्च वार्षिकी दर प्रदान करती है।
vi.अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके वार्षिकी भी बढ़ाई जा सकती है।
vii.योजना को पहले अनपेड प्रीमियम की तारीख से लगातार 5 वर्षों के भीतर भी पुनर्जीवित किया जा सकता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के बारे में:

अंतरिम अध्यक्ष – सिद्धार्थ मोहंती
मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
स्थापना – 1956

सरकार ने IFSC GIFT सिटी में फाइनेंसियल सर्विसेज का दायरा बढ़ाया; 4 अतिरिक्त सर्विसेज अधिसूचित किया

मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत सरकार (GoI) ने गांधीनगर, गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी **(GIFT सिटी)** में भारत के पहले इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर **(IFSC)** में दी जाने वाली फाइनेंसियल सर्विसेज के दायरे का विस्तार किया है।

- फाइनेंसियल सर्विसेज के एक भाग के रूप में **4 अतिरिक्त सर्विसेज** - फाइनेंसियल क्राइम कम्प्लायंस, कराधान, लेखांकन और बहीखाता - अधिसूचित की गईं।

प्रमुख बिंदु:

i.ये 4 अतिरिक्त सर्विसेज GIFT सिटी या IFSC में इकाइयों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी, जो इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर्स ऑथोरिटी **(IFSCA)** द्वारा विनियमित हैं, जिसमें संस्थाओं को कर लाभ उपलब्ध हैं।

ii.ये सर्विसेज गैर-निवासियों (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारत के बाहर निवासी व्यक्ति) को प्रदान की जा सकती हैं जिनका व्यवसाय भारत में मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्निर्माण या पुनर्गठित करके स्थापित नहीं किया गया है।

iii.GIFT सिटी में IFSC के भीतर मौजूदा इकाइयां भी इन सर्विसेज का लाभ उठा सकती हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

i.फाइनेंसियल क्राइम कम्प्लायंस सर्विसेज में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग **(AML)** के अनुपालन और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (CFT) उपायों और फाइनेंसियल एक्शन टास्क फॉर्स (FATF) की सिफारिशों और अन्य संबंधित गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए प्रदान की गई सर्विसेज शामिल हैं।

ii.इससे GIFT सिटी में हथियारों के माध्यम से अपनी कुछ सर्विसेज प्रदान करने के लिए चार बड़ी कंपनियों - डेलॉइट, KPMG, EY(अर्नस्ट & यंग), और PwC (प्राइसवाटरहाउसकूपर्स) को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (GIFT-सिटी)के बारे में :

MD & ग्रुप CEO - तपन रे

अध्यक्ष – डॉ. हसमुख अधिया

मुख्यालय– गांधीनगर, गुजरात

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अनुकूलन योग्य वार्षिकी विकल्पों के साथ 'SWAG पेंशन प्लान' लॉन्च की

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(मैक्स लाइफ)** ने "मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी प्लान" **(SWAG पेंशन प्लान)** लॉन्च किया, जो ग्राहकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार वार्षिकी विकल्पों की एक श्रृंखला में से चयन करते हुए, अपनी नीतियों को तैयार करने की पेशकश करता है।

- SWAG पेंशन प्लान एक गैर-लिंक्ड, गैर-भागीदारी वाली व्यक्तिगत/समूह सामान्य वार्षिकी बचत प्लान है।

SWAG पेंशन प्लान के बारे में:

i.SWAG पेंशन प्लान सेवानिवृत्ति प्लान में क्रांति लाती है, लचीलेपन, सुरक्षा और वैयक्तिकरण का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करती है।

ii.इस प्लान के साथ, ग्राहकों को 'प्रीमियम की वापसी' विकल्पों की एक श्रृंखला से चयन करने की भी स्वतंत्रता मिल सकती है।

विशेषताएँ:

यह प्लान सुविधाओं का एक सेट प्रदान करती है जिसमें शामिल हैं,

i.ग्राहक की सेवानिवृत्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वार्षिकी विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला।

ii.जीवित वार्षिकीधारक या नामांकित व्यक्ति के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के चयनित अनुपात की वापसी तय करने के लचीलेपन के साथ तत्काल वार्षिकी।

iii.प्रति वर्ष 6% तक वार्षिकी बढ़ाना बढ़ती मुद्रास्फीति के लिए तत्परता सुनिश्चित करता है।

iv.प्रीमियम की शीघ्र वापसी के साथ लचीलापन प्राप्त करें, अलग-अलग मील के पत्थर की आयु 70 से 85 वर्ष (5-वर्ष ब्लॉक में) तक हो।

v.जीवित वार्षिकीग्राही को प्रथम वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर अग्रिम रूप से वार्षिकी का एक चयनित अनुपात वापस लेने का विकल्प प्रदान करें।

vi.ग्राहक जल्दी प्लान बना सकते हैं और पहले महीने से 12 साल तक के लिए पहले वार्षिकी भुगतान को स्थगित करके सेवानिवृत्ति पर उच्च वार्षिकी प्राप्त कर सकते हैं।

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मैक्स लाइफ) के बारे में:

मैक्स लाइफ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम (JV) है।

प्रबंध निदेशक (MD) & मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)- प्रशांत त्रिपाठी

मुख्यालय–गुरुग्राम, हरियाणा

सामान्य बीमा परिषद ने "कैशलेस एवरीवेयर" पहल शुरू की

सामान्य बीमा परिषद (**GIC**) ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के परामर्श से '**कैशलेस एवरीवेयर**' पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य सभी अस्पतालों में कैशलेस उपचार का विस्तार करना है, जिससे संपूर्ण दावों की यात्रा एक बाधा रहित प्रक्रिया बन जाएगी।

- यह पहल सभी अस्पतालों को कैशलेस अस्पताल में भर्ती लाभ प्रदान करती है, जिनमें वे अस्पताल भी शामिल हैं जिनका बीमा कंपनियों के साथ गठजोड़ नहीं है।
- पहल के तहत बीमा का दावा करने के लिए, ग्राहक को वैकल्पिक प्रक्रियाओं के लिए प्रवेश से 48 घंटे पहले और आपातकालीन उपचार के मामले में प्रवेश के **48 घंटे** बाद अपने बीमाकर्ता को सूचित करना चाहिए।
- यह पहल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत पंजीकृत 15+ बिस्तरों वाले अस्पतालों पर लागू होती है।
- कैशलेस सुविधा बीमाकर्ता के परिचालन दिशानिर्देशों के अधीन है।

केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने iSelect गारंटीड फ्यूचर प्लस लॉन्च किया

केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, व्यक्तिगत बचत लाइफ इंश्योरेंस प्लान '**iSelect गारंटीड फ्यूचर प्लस**' लॉन्च की है।

प्लान के बारे में:

पॉलिसी चार अलग-अलग प्लान , जैसे बंदोबस्ती विकल्प, नियमित आय विकल्प, प्रारंभिक आय विकल्प और प्रीमियम रिटर्न के साथ दीर्घकालिक आय विकल्प पेश करती है।

पात्रता:

i.न्यूनतम प्रवेश आयु- NIL

ii.अधिकतम प्रवेश आयु- 65 वर्ष

iii.न्यूनतम परिपक्वता आयु - 18 वर्ष

iv.अधिकतम परिपक्वता आयु - 99 वर्ष

बंदोबस्ती विकल्प:

i.यह प्लान पॉलिसीधारकों को गारंटीशुदा परिपक्वता लाभ के साथ लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करती है।

पॉलिसी अवधि के अंतिम पांच वर्षों के दौरान अतिरिक्त गारंटी भी दी जाएगी

ii.यह प्लान लचीली प्रीमियम भुगतान अवधि (PPT)/पॉलिसी अवधि (PT) भी प्रदान करती है।

iii.पॉलिसीधारक वैकल्पिक लाभों - भुगतानकर्ता प्रीमियम सुरक्षा कवर या दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB) में से एक चुन सकता है।

नियमित आय विकल्प:

i.यह प्लान गारंटीकृत आय और परिपक्वता लाभ के साथ लाइफ इंश्योरेंस सेवाएं प्रदान करती है।

ii.प्लान PPT के बाद गारंटीकृत आय भुगतान की पेशकश करती है।

iii.पॉलिसीधारक भुगतानकर्ता प्रीमियम सुरक्षा कवर या ABD में से किसी एक को चुन सकता है।
iv.प्लान लचीली PPT/PT भी प्रदान करती है।

प्रारंभिक आय विकल्प:

i.यह प्लान दूसरे पॉलिसी वर्ष से गारंटीकृत आय के अतिरिक्त लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करती है।
ii.ABD डिफ़ॉल्ट रूप से योजना के साथ आता है।
iii.पॉलिसीधारकों को अपनी आय अवधि और PPT चुनने की अनुमति है।

प्रीमियम विकल्प की वापसी के साथ दीर्घकालिक आय:

i.यह योजना इनबिल्ड ABD सुविधा के साथ गारंटीकृत आय (समेकन अवधि के बाद) के साथ लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करती है।
ii.पॉलिसी परिपक्व होने पर भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 100% वापस कर दिया जाएगा।
iii.पॉलिसी आय अवधि और आय प्रारंभ अवधि चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करती है।
नोट- ये सभी योजनाएं समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के तहत कर लाभ प्रदान करती हैं।

केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में:

केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केनरा बैंक (51%) और HSBC इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग्स लिमिटेड (26%) द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम **(JV)** है।
प्रबंध निदेशक (MD) & मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) - अनुज माथुर
मुख्यालय-गुरुग्राम, हरियाणा
स्थापित - 2008

ECONOMY & BUSINESS NEWS

FY24 में भारत की GDP वृद्धि 6.5% से अधिक होगी: DEA

वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ़ इकनोमिक अफेयर्स (DEA) द्वारा जारी "हाफ-इयरली इकनोमिक रिव्यु 2023-24-नवंबर 2023" में उल्लेख किया गया है कि वित्त वर्ष 2023-2024 (**FY24**) की फर्स्ट हाफ (**H1**) में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) **7.7%** बढ़ा है। इससे **FY24** में भारत के **6.5% से अधिक** की विकास दर हासिल करने की उम्मीद है।

- FY24 की दूसरी तिमाही (Q2) में भारत की वास्तविक GDP साल-दर-साल (**YoY**) आधार पर 7.6% बढ़ी |

प्रमुख बिंदु:

i.FY24 की H1 के दौरान GDP की वृद्धि खपत और निवेश की मजबूत घरेलू मांग के कारण हुई।
ii.निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में 4.5% की वृद्धि हुई, जो GDP के 60.4% तक पहुंच गया, जो FY21 को छोड़कर, FY12 के बाद से सबसे अधिक है।
iii.GDP (वर्तमान मूल्य) में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (**GFCF**) की हिस्सेदारी FY23 की H1 में 29.1% से बढ़कर FY24 की H1 में 29.6% हो गई।
iv.केंद्र का पूंजीगत व्यय अप्रैल-अक्टूबर FY24 में FY23 की इसी अवधि की तुलना में 33.7% बढ़ गया।
v.GVA(सकल मूल्य वर्धित) Q2FY24 में 7.4% की वृद्धि हुई, जिसने FY24 में H1 में 7.6% की वृद्धि दर्ज की। उद्योग खंड (GVA के घटक) ने H1FY24 में 9.3% की वृद्धि दर्ज की।

- यह उप-घटक खनन और उत्खनन, विनिर्माण और निर्माण में क्रमशः **7.6%, 9.3%** और **10.5%** की ठोस वृद्धि से प्रेरित था।

vi.पूंजीगत वस्तुओं और निर्माण क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) FY24 की H1 में 6.1% बढ़ गया।
vii.सेवा निर्यात में सकारात्मक प्रदर्शन के साथ, FY24 की H1 में सेवा क्षेत्र में 8% की वृद्धि हुई।

मुख्य विशेषताएं:

i.FY24 की Q3 और A4 में निरंतर विकास गति की उम्मीद है।
ii.बेरोजगारी दर H2FY23 में 7% से घटकर H1FY24 में 6.6% हो गई।
iii.H1FY24 में व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में 8.8% की गिरावट आई।
iv.कुल व्यापार घाटा H1FY23 में 75.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर H1FY24 में 39.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
v.भारत में सकल FDI प्रवाह H1FY24 में 15.9% कम था।
vi.आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) से संबंधित परियोजनाओं में 2016 के बाद से इस क्षेत्र में वैश्विक निवेश का 26.2% हिस्सा है।
vii.मुद्रास्फीति H1FY23 में 7.2% से घटकर H1FY24 में 5.5% हो गई।
viii.शहरी बेरोजगारी दर H1FY23 में 7.4% से घटकर H1FY24 में 6.6% हो गई।
ix.सरकार का शुद्ध कर राजस्व H1FY24 में YoY 11.2% बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपये हो गया।

वित्त मंत्रालय के बारे में:

केंद्रीय मंत्री– निर्मला सीतारमण (राज्यसभा, कर्नाटक)
राज्य मंत्री– भागवत किशनराव कराड; पंकज चौधरी

इंडिया रेटिंग्स ने FY24 के लिए भारत की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान 6.2% से 6.7% बढ़ाया है

3 जनवरी, 2024 को, फिच ग्रुप का हिस्सा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च **(Ind-Ra)** प्राइवेट लिमिटेड ने 2023-2024 (**FY24**) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (**GDP**) के वृद्धि अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।

कारक:

GDP पूर्वानुमान में वृद्धि विभिन्न कारकों के कारण होती है, जैसे,
i.भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीलापन, जो 1QFY24 में 7.8% YoY बढ़ने के बाद, दूसरी तिमाही (Q2FY24) में 7.6% YoY बढ़ी।
ii.स्थायी सरकार (पूंजीगत व्यय)।
iii.एक नए निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय चक्र की संभावना।
iv.बाकी दुनिया से प्रेषण के साथ-साथ व्यापार और सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में निरंतर गति।

प्रमुख बिंदु:

i.भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर वैश्विक व्यापार और आर्थिक वृद्धि के कारण निर्यात में कमी की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
ii. Ind-Ra ने FY24 के लिए GDP वृद्धि अनुमान को अक्टूबर 2023 में 5.9% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया।
iii.इंडिया रेटिंग्स को उम्मीद है कि चालू खाता घाटा FY23 में 2.0% से घटकर FY24 में GDP का 1.3% हो जाएगा।
iv.FY24 में माल निर्यात में 9.3% YoY(वर्ष-दर-वर्ष) गिरावट की उम्मीद है; माल आयात में YoY आधार पर 7.9% की गिरावट।
v.अनिश्चित बाहरी मांग के कारण व्यापार घाटा 260.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 7.3%) अनुमानित है।

वैश्विक परिदृश्य:

i.उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति सख्त होने के बीच वैश्विक वृद्धि के लिए जोखिम है।

- इसके परिणामस्वरूप 2023 में वैश्विक मुद्रास्फीति घटकर 6.9% और 2024 में 5.8% (2022: 8.7%) हो सकती है।

ii.अस्थिर भू-राजनीतिक स्थिति, वैश्विक वृद्धि और व्यापार को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के माध्यम से

iii.विश्व व्यापार संगठन (WTO) को उम्मीद है कि विश्व व्यापारिक व्यापार की मात्रा 2023 में अनुमानित 1.7% की तुलना में केवल 0.8% बढ़ी है।

iv.अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को उम्मीद है कि 2024 में वैश्विक वृद्धि धीमी होकर 2.9% (2023: 3 प्रतिशत) हो जाएगी, जो महामारी से पहले की औसत वृद्धि 3.8% (2000-19) से कम है।

ओला इलेक्ट्रिक PLI योजना के लिए पात्र पहली भारतीय e2W कंपनी बन गई

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (**ओला**), भारी उद्योग मंत्रालय (**MHI**) से मंजूरी मिलने के बाद प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (**PLI**) योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (**e2W**) कंपनी बन गई है।

i.PLI सर्टिफिकेशन ओला को प्रति यूनिट 15,000 रुपये से 18,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करता है।

ii.यह वित्तीय प्रोत्साहन पूरे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा।

iii.ओला इलेक्ट्रिक ने PLI योजना में उल्लिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिसमें उसके व्हीकल्स में न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन शामिल है।

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में:

सह-संस्थापक– भाविश अग्रवाल (CEO) & अंकित भाटी

मुख्यालय – बेंगलुरु, कर्नाटक

स्थापित – 2017

FY24 में भारत की GDP 7.3% बढ़ने की संभावना: NSO द्वारा फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्द

5 जनवरी, 2024 को, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (**NSO**), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (**MoSPI**) ने स्थिर (2011-12) और वर्तमान कीमतों दोनों पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स (FAE) ऑफ नेशनल इनकम फॉर द फाइनेंसियल ईयर 2023-24 जारी किया।

- इसके अनुसार, वास्तविक GDP में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि FY24 में **7.3%** होगी, जबकि FY23 में यह 7.2% थी।
- जबकि नाममात्र के संदर्भ में, FY24 में भारत के लिए अनुमानित GDP की वृद्धि 8.9% है, जो कि FY23 में दर्ज 16.1% से कम है।

नोट्स:

i.भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

ii.यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि FY24 में भारत की 7% वृद्धि दर लगातार तीसरा वर्ष है।

iii.उच्च GDP की वृद्धि सरकारी व्यय के साथ-साथ खनन, विनिर्माण, निर्माण और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रीय आउटपुट में बढ़ोतरी से प्रेरित है।

- कृषि और व्यापार, होटल, परिवहन और संचार सेवाएं धीमी गति से चल रही हैं।

iv.केंद्र सरकार का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 7% के उन्नत पूर्वानुमान से अधिक है।

मुख्य विचार:

i.वास्तविक GDP या GDP स्थिर (2011-12) कीमतों पर FY24 में **171.79 लाख करोड़ रुपये** होने का अनुमान है, जबकि 31 मई, 2023 को जारी FY23 के लिए GDP का अनंतिम अनुमान 160.06 लाख करोड़ रुपये है।

ii.FY24 में मौजूदा कीमतों पर नाममात्र GDP या GDP **296.58 लाख करोड़** रुपये होने का अनुमान है, जबकि FY23 के लिए GDP का अनंतिम अनुमान 272.41 लाख करोड़ रुपये है।

- नाममात्र GDP में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है, और इसलिए डेटा मुद्रास्फीति में गिरावट दर्शाता है

iii.FY24 में उपभोग मांग कमजोर है। निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) 2023-24 में 4.4% बढ़ने की उम्मीद है।

- PFCE विकास दर का पिछला निचला स्तर 2002-03 में 2.9% था, जबकि FY23 में यह 7.5% की दर से बढ़ा।

iv.इसके विपरीत, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (GFCE) FY24 में तेजी से बढ़कर 4.1% होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 0.1% था।

v.सकल निश्चित पूंजी निर्माण (**GFCF**) द्वारा दर्शाई गई निवेश मांग में वृद्धि FY23 में 11.4% से कम होकर 10.3% होने का अनुमान है।

vi.FY24 में उत्पादों पर शुद्ध करों में वृद्धि 12.5% अनुमानित है, जबकि FY23 में यह 10.1% थी।

आर्थिक गतिविधि के आधार पर मूल कीमतें (2011-12 की कीमतों पर)

उद्योग	**पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन**	
	2022-23	**2023-24**
उत्पादन	1.3	6.5
निर्माण	10	10.7
खनन & उत्खनन	4.6	8.1
कृषि, पशुधन, वानिकी & मत्स्य पालन	4	1.8
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	14	6.3
वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ	7.1	8.9

आकलन:

एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम FY24 के पहले सात-आठ महीनों और FY23 डेटा का उपयोग करके निकाला जाता है। यह प्रारंभिक रिलीज़ केंद्रीय वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के अधिकारियों को FY2025 के लिए आगामी केंद्रीय बजट के प्रमुख पहलुओं को आकार देने में सहायता करती है, जिसे 1 फरवरी, 2024 को संसद में प्रस्तुत किया जाना है।

हाल के संबंधित समाचार:

i.9 अक्टूबर, 2023 को, NSO ने अप्रैल-जून 2023 (Q1FY24) के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का अपना 19वां क्वार्टरली बुलेटिन (QB) जारी किया। इसके अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के संदर्भ में भारत की शहरी बेरोजगारी दर (UR) Q1FY24 के दौरान Q4FY23 के दौरान 6.8% से घटकर 6.6% हो गई। अप्रैल-जून 2022 (Q1FY23) में यह 7.6% थी।

ii.आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा प्रकाशित "इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक: 2023" के अनुसार, लगातार दूसरे वर्ष, भारत ने 2021 में OECD के सदस्य देशों में नए प्रवासियों के लिए मूल के शीर्ष देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के बारे में:

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)– राव इंद्रजीत सिंह (निर्वाचन क्षेत्र-गुरुग्राम, हरियाणा)

सचिव- डॉ. G P सामंत

FY24 में भारत की GDP 7.3% बढ़ने की संभावना: NSO द्वारा फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्द

5 जनवरी, 2024 को, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (**NSO**), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (**MoSPI**) ने स्थिर (2011-12) और वर्तमान कीमतों दोनों पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स (FAE) ऑफ नेशनल इनकम फॉर द फाइनेंसियल ईयर 2023-24 जारी किया।

- इसके अनुसार, वास्तविक GDP में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि FY24 में **7.3%** होगी, जबकि FY23 में यह 7.2% थी।
- जबकि नाममात्र के संदर्भ में, FY24 में भारत के लिए अनुमानित GDP की वृद्धि 8.9% है, जो कि FY23 में दर्ज 16.1% से कम है।

नोट्स:

i.भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

ii.यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि FY24 में भारत की 7% वृद्धि दर लगातार तीसरा वर्ष है।

iii.उच्च GDP की वृद्धि सरकारी व्यय के साथ-साथ खनन, विनिर्माण, निर्माण और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रीय आउटपुट में बढ़ोतरी से प्रेरित है।

- कृषि और व्यापार, होटल, परिवहन और संचार सेवाएं धीमी गति से चल रही हैं।

iv.केंद्र सरकार का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 7% के उन्नत पूर्वानुमान से अधिक है।

मुख्य विचार:

i.वास्तविक GDP या GDP स्थिर (2011-12) कीमतों पर FY24 में **171.79 लाख करोड़ रुपये** होने का अनुमान है, जबकि 31 मई, 2023 को जारी FY23 के लिए GDP का अनंतिम अनुमान 160.06 लाख करोड़ रुपये है।

ii.FY24 में मौजूदा कीमतों पर नाममात्र GDP या GDP **296.58 लाख करोड़** रुपये होने का अनुमान है, जबकि FY23 के लिए GDP का अनंतिम अनुमान 272.41 लाख करोड़ रुपये है।

- नाममात्र GDP में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है, और इसलिए डेटा मुद्रास्फीति में गिरावट दर्शाता है

iii.FY24 में उपभोग मांग कमजोर है। निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) 2023-24 में 4.4% बढ़ने की उम्मीद है।

- PFCE विकास दर का पिछला निचला स्तर 2002-03 में 2.9% था, जबकि FY23 में यह 7.5% की दर से बढ़ा।

iv.इसके विपरीत, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (GFCE) FY24 में तेजी से बढ़कर 4.1% होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 0.1% था।

v.सकल निश्चित पूंजी निर्माण (**GFCF**) द्वारा दर्शाई गई निवेश मांग में वृद्धि FY23 में 11.4% से कम होकर 10.3% होने का अनुमान है।

vi.FY24 में उत्पादों पर शुद्ध करों में वृद्धि 12.5% अनुमानित है, जबकि FY23 में यह 10.1% थी।

आर्थिक गतिविधि के आधार पर मूल कीमतें (2011-12 की कीमतों पर)

उद्योग	पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन	
	2022-23	2023-24
उत्पादन	1.3	6.5

निर्माण	10	10.7
खनन & उत्खनन	4.6	8.1
कृषि, पशुधन, वानिकी & मत्स्य पालन	4	1.8
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	14	6.3
वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ	7.1	8.9

आकलन:

एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम FY24 के पहले सात-आठ महीनों और FY23 डेटा का उपयोग करके निकाला जाता है। यह प्रारंभिक रिलीज़ केंद्रीय वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के अधिकारियों को FY2025 के लिए आगामी केंद्रीय बजट के प्रमुख पहलुओं को आकार देने में सहायता करती है, जिसे 1 फरवरी, 2024 को संसद में प्रस्तुत किया जाना है।

हाल के संबंधित समाचार:

i.9 अक्टूबर, 2023 को, NSO ने अप्रैल-जून 2023 (Q1FY24) के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का अपना 19वां क्वार्टरली बुलेटिन (QB) जारी किया। इसके अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के संदर्भ में भारत की शहरी बेरोजगारी दर (UR) Q1FY24 के दौरान Q4FY23 के दौरान 6.8% से घटकर 6.6% हो गई। अप्रैल-जून 2022 (Q1FY23) में यह 7.6% थी।

ii.आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा प्रकाशित "इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक: 2023" के अनुसार, लगातार दूसरे वर्ष, भारत ने 2021 में OECD के सदस्य देशों में नए प्रवासियों के लिए मूल के शीर्ष देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के बारे में:

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)– राव इंद्रजीत सिंह (निर्वाचन क्षेत्र-गुरुग्राम, हरियाणा)

सचिव- डॉ. G P सामंत

ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज लिमिटेड सितंबर 2024 से भारत के FAR बॉन्ड्स को अपने EM इंडेक्स में शामिल करेगा

ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज लिमिटेड **(BISL)** ने अपने उभरते बाजार **(EM)** लोकल करेंसी इंडेक्स में भारत के पूर्णतया सुगम्य मार्ग **(FAR)** बॉन्ड्स को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के अनुसार, भारत सरकार के बॉन्ड्स को शामिल करना सितंबर 2024 से शुरू होकर 5 महीने तक चलने वाली एक चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना होगी।

- प्रत्येक माह FAR श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बॉन्ड्स के पूर्ण बाजार मूल्य(100%) का 20% जोड़ा जाएगा जिसमें विदेशी निवेशकों पर कोई प्रतिबंध शामिल नहीं है। यह प्रक्रिया जनवरी 2025 में पूरी हो जाएगी|
- एक बार ब्लूमबर्ग EM 10% कंट्री कैप्ड इंडेक्स में पूरी तरह से शामिल हो जाने के बाद, भारत FAR बॉन्ड्स इंडेक्स के भीतर 10% भार पर पूरी तरह से कैप हो जाएंगे।
- उस समय, ब्लूमबर्ग EM लोकल करेंसी इंडेक्स के भीतर चीनी रेनमिनबी और दक्षिण कोरियाई वोन के बाद भारतीय रुपया तीसरा सबसे बड़ा करेंसी घटक बन जाएगा।

नोट:

- भारत के FAR बॉन्ड्स वे हैं जिन्हें विदेशी निवेशक बिना किसी सीमा के खरीद सकते हैं।
- सितंबर 2023 में, JP मॉर्गन ने कहा कि भारत सरकार के बॉन्ड जून 2024 से उसके सरकारी बॉन्ड इंडेक्स-EM (GBI-EM) ग्लोबल इंडेक्स सूट का हिस्सा होंगे।

FY25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.2% की दर से बढ़ेगी: UBS सिक्योरिटीज

मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित UBS सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (**FY25**) के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.3% से घटाकर **6.2%** कर दी है।

- भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) FY25 में 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो FY24 में 3.57 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- FY25 में उपभोग वृद्धि 4.7% पर स्थिर होने का अनुमान है, जबकि FY24 में यह 4.5% थी।
- 15 साल के उच्च घरेलू ऋण स्तर के बीच तटस्थ नीति सेटिंग्स, सकारात्मक ऋण गति और प्रबंधनीय मैक्रोज़ द्वारा विकास को प्रेरित किया गया है।

NSE 2023 में लगातार 5वें वर्ष विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज; इक्विटी सेगमेंट में तीसरा बना रहा

फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन **(FIA)** द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **(NSE)** कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या के मामले में **2023** में **दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज** बनकर उभरा है। NSE ने लगातार 5वें साल खिताब बरकरार रखा है।

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज (WFE) द्वारा बनाए गए आंकड़ों के अनुसार, NSE 2023 में ट्रेडों की संख्या

- (इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक) के हिसाब से इक्विटी सेगमेंट में दुनिया में तीसरे स्थान पर है।

नोट: NSE भारत में इलेक्ट्रॉनिक या स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग लागू करने वाला पहला एक्सचेंज था।

2023 माइलस्टोन:

i.सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया;

ii.लघु और मध्यम आकार के उद्यम (SME) सूचीबद्ध कंपनियों ने 1,00,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया; और

iii.पहली बार, निफ्टी 50 इंडेक्स 20,000 इंडेक्स स्तर को पार कर गया।

iv.कैलेंडर वर्ष 2023 के अंत में एक्सचेंज पर अद्वितीय पंजीकृत निवेशकों की संख्या 8.5 करोड़ से अधिक हो गई।

टर्नओवर:

i.अपने इक्विटी सेगमेंट में, NSE ने 2014 से 2023 तक लगातार 10वें वर्ष कारोबार करने वाले ग्राहकों की संख्या में साल-दर-साल (Y-O-Y) वृद्धि देखी।

ii.2022 में 2.86 से मामूली गिरावट के बावजूद, 2023 में इक्विटी डेरिवेटिव और नकद बाजार टर्नओवर अनुपात 2.64 है।

बाज़ार विकास:

i.इक्विटी खंड T+1 आधार पर सभी प्रतिभूतियों के निपटान के लिए अपना परिवर्तन पूरा करता है, जिससे दक्षता बढ़ती है।

ii.प्राथमिक बाजार में, प्रतिभूतियों की लिस्टिंग की समयसीमा को घटाकर T+3 दिन कर दिया गया है, जिससे निवेशकों के लिए त्वरित पहुंच की सुविधा मिल गई है।

नवोन्वेषी पेशकश:

NSE ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च किया, जो गैर-लाभकारी संगठनों (NPO) और वित्त पोषित परोपकारी उद्यमों (FPE) जैसे सामाजिक उद्यमों के लिए एक मंच प्रदान करता है।

- इसका उद्देश्य अपने काम का प्रदर्शन करना और जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बांड जैसे उपकरण जारी करके धन जुटाना है।

नोट: इस खंड में 42 NPO द्वारा पंजीकरण और एक NPO द्वारा सफल धन उगाही देखी गई है।

कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सपेंशन:

NSE ने 21 नए कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध पेश किए, जिनमें WTI कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, चांदी और बेस मेटल जैसी वस्तुओं के लिए वायदा अनुबंध पर कमोडिटी विकल्प शामिल हैं।

इंटरनेशनल एक्सपेंशन:

NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज (NSE IX) ने NSE IX-SGX GIFT कनेक्ट का पूर्ण पैमाने पर संचालन शुरू किया, एशिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका (US) के व्यापारिक घंटों को कवर करते हुए निफ्टी उत्पाद व्यापार को लगभग 21 घंटे तक बढ़ा दिया।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NSE) के बारे में:

NSE को 1992 में शामिल किया गया था; अप्रैल 1993 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्राप्त; और 1994 में परिचालन शुरू किया।

MD & CEO - आशीषकुमार चौहान

मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र

ICRA का अनुमान है कि FY 2023-24 की Q3 में GDP की वृद्धि दर मध्यम होकर 6% से नीचे रहेगी

ICRA लिमिटेड (पूर्व में इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड) का अनुमान है कि FY 2024 की तीसरी तिमाही (Q3) (अक्टूबर से दिसंबर 2023) में भारत की सकल घरेलू उत्पाद **(GDP)** की वृद्धि **6% से कम** हो सकती है, जो FY 2024 की दूसरी तिमाही (Q2) में 7.6% थी।

- इस गिरावट का मुख्य कारण खरीफ फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय अवनति और कुछ फसलों की रबी बुआई में कमज़ोर प्रगति है।

GDP की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक:

पूंजीगत व्यय में गिरावट: ICRA ने अक्टूबर-नवंबर 2023 (Q3 में) में सरकार के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में -8.8% साल-दर-साल (YoY) गिरावट दर्ज की है।

कृषि GVA अनुमान: खरीफ फसल उत्पादन में तेज गिरावट और रबी बुआई में कमजोर प्रगति के कारण कृषि सकल मूल्य वर्धित (GVA) में बहुत कम या ना के बराबर वृद्धि की आशंका।

आर्थिक संकेतक अवलोकन:

i.1-16 जनवरी, 2024 तक औसत दैनिक वाहन पंजीकरण एक साल पहले की अवधि की तुलना में 39.2% अधिक था।

ii.हालाँकि, वे दिसंबर 2023 में 6,46,000 इकाइयों/दिन के पंजीकरण से 1.8% कम थे, जिसका कारण अशुभ खरमास अवधि और मौसमी था।

iii.बिजली की मांग में Y-O-Y वृद्धि दिसंबर 2023 में 1.6% से जनवरी 2024 (15 जनवरी तक) में मामूली रूप से बढ़कर 3.4% हो गई, ऊंचे आधार के कारण धीमी रही।

ICRA बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटर एनालिसिस:

विकास में गिरावट: ICRA बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटर में Y-O-Y वृद्धि दिसंबर 2023 में 6 महीने के निचले स्तर 8.1% पर पहुंच गई, जो दिसंबर 2022 में 7.9% और नवंबर 2023 में 9.6% थी।

गिरावट में योगदान देने वाले कारक: उत्सव के बाद की अवधि में गतिविधि की गति में कमी; उत्तर भारत में सर्दी शुरू होने से बिजली और पेट्रोल की मांग में कमी; और कुछ संकेतकों के लिए प्रतिकूल आधार प्रभाव।

बिजनेस एक्टिविटी में क्रमिक वृद्धि:

i.Y-O-Y वृद्धि में नरमी के बावजूद, बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटर ने दिसंबर 2023 में 1.4% की क्रमिक वृद्धि का अनुभव किया, जो 14 गैर-वित्तीय संकेतकों में से 8 द्वारा संचालित था।

ii.ICRA ने चालू वित्तीय वर्ष की Q3 में स्वस्थ आर्थिक गतिविधि देखी है, लेकिन पिछली तिमाही की तुलना में नरमी को स्वीकार किया है, जो आंशिक रूप से आधार सामान्यीकरण के कारण है।

भारत बना चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार, हांगकांग को पछाड़ा

बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है, भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

- भारत ने **हांगकांग** को पीछे छोड़ दिया है जिसके शेयरों का संयुक्त मूल्य 4.29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- शीर्ष तीन शेयर बाज़ार क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), चीन और जापान हैं।

BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को "BOBCARD लिमिटेड" के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) की पूर्ण स्वामित्व वाली कार्ड कंपनी BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड को टैगलाइन "क्रेडिट रीइमेजिन्ड" के साथ 'BOBCARD लिमिटेड' के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया है।

- यह 1994 में स्थापित एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी **(NBFC)** है।
- 'BOBCARD लिमिटेड' के लिए **'बड़ौदा सन'** नामक नए लोगो का भी अनावरण किया गया। लोगो में दोहरे 'B' अक्षर शामिल हैं जो उगते सूरज की किरणों को धारण करते हैं।
- BOBCARD उपभोक्ता और वाणिज्यिक क्रेडिट कार्डों की एक श्रृंखला प्रदान करता है और भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक और असम राइफल्स जैसे रक्षा कर्मियों सहित सभी वर्गों के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, BOBCARD लिमिटेड के पास दिसंबर 2023 तक 22.4 लाख बकाया क्रेडिट कार्ड थे।

टीटागढ़ रेल सिस्टम, एम्बर ग्रुप ने संयुक्त SPV के लिए हाथ मिलाया

कोलकाता, पश्चिम बंगाल की **टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड (TRSL)** और दिल्ली स्थित **एम्बर ग्रुप** ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी **सिडवाल रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड** के माध्यम से साझा सेवाओं के लिए एक संयुक्त विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) स्थापित करने के लिए सहयोग किया है।

i.SPV रेलवे और मेट्रो कोचों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण रेलवे घटकों और उप-प्रणालियों के निर्माण के लिए भारत में एक नई सुविधा स्थापित करेगा।

ii.इस सहयोग के हिस्से के रूप में, इटली में टीटागढ़फायरमा SpA, टीटागढ़ ग्रुप की एक सहयोगी कंपनी है जहां सरकार। इटली का भी एक इक्विटी हिस्सेदारी धारक है।

iii.TRSL और एम्बर ग्रुप दोनों नए रेलवे घटक व्यवसाय की स्थापना के साथ-साथ फायरमा, इटली में नए इक्विटी निवेश के लिए SPV में लगभग 50% प्राप्त करने के लिए लगभग 120 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।

iv.समझौते के तहत, फायरमा **सिडवाल, टीटागढ़ रेल** के साथ-साथ SPV को उनके सभी उत्पादों के लिए पसंदीदा आपूर्तिकर्ता का दर्जा और **पहले इनकार का अधिकार (ROFR)** प्रदान करेगा।

MoU's & AGREEMENTS

भारत & सऊदी अरब ने जेद्दा में द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए

7 जनवरी 2024 को, भारत और सऊदी अरब साम्राज्य ने **द्विपक्षीय हज समझौते 2024** पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत हज 2024 के लिए भारत से कुल **1,75,025 तीर्थयात्रियों** के कोटे को अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें हज समिति के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए 1,40,020 सीटें आरक्षित हैं, जबकि 35,005 तीर्थयात्रियों को निजी ऑपरेटरों के माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

हस्ताक्षरकर्ता: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और सऊदी अरब के जेद्दा में हज और उमराह के सऊदी मंत्री डॉ. तौफीक बिन फावज़ान ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री (MoS) V मुरलीधरन की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ध्यान देने योग्य बातें:

i.केंद्रीय मंत्री ईरानी & MoS हज मुरलीधरन ने तीर्थयात्रियों की व्यवस्था की निगरानी के लिए किंग अब्दुलअज़ीज़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जेद्दा के टर्मिनल का दौरा किया।

ii.8 जनवरी 2024 को, केंद्रीय मंत्री ईरानी ने जेद्दा में सऊदी हज और उमरा मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित तीसरे 'हज और उमरा सम्मेलन' के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

भारत और U.K. ने क्रमशः R&D और कैडेट विनिमय कार्यक्रम में रक्षा सहयोग के लिए LoA और MoU पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 & 10 जनवरी 2024 को यूनाइटेड किंगडम (U.K.) की दो दिवसीय यात्रा की और अपने ब्रिटिश काउंटरपार्ट ग्रांट शाप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस यात्रा में दोनों देशों द्वारा LoA और MoU पर हस्ताक्षर भी किये गये।

द्विपक्षीय बैठक के परिणामस्वरूप भारत और U.K. के बीच दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

i.द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट विनिमय कार्यक्रम के संचालन पर भारत और U.K. के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

ii.अनुसंधान और विकास (R&D) में रक्षा सहयोग पर **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)**, भारत और **रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (DSTL)**, U.K. के बीच व्यवस्था पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

इन समझौतों का महत्व:

i.ये समझौते विशेष रूप से युवाओं के बीच लोगों से लोगों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे और बढ़ावा देंगे।

ii.यह भारत और U.K. के बीच रक्षा अनुसंधान सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करेगा।

नोट: यह 20 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की U.K. की पहली यात्रा है (इससे पहले 2002 में MoD जॉर्ज फर्नांडीस ने दौरा किया था)।

रक्षा मंत्रालय के बारे में:

केंद्रीय मंत्री: राजनाथ सिंह (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र: लखनऊ, उत्तर प्रदेश)

राज्य मंत्री (MoS): अजय भट्ट (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र: नैनीताल-उधमसिंह नगर, उत्तराखंड)

यूनाइटेड किंगडम (U.K.) के बारे में:

प्रधान मंत्री: ऋषि सुनक

राजधानी: लंदन

मुद्रा: द पाउंड स्टर्लिंग (GBP)

रक्षा अनुसंधान विकास और संगठन (DRDO) के बारे में:

अध्यक्ष: डॉ. समीर वेंकटपति कामत

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली

स्थापना: 1958

डेनमार्क ने भारत के साथ साझेदारी में ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया लॉन्च किया

डेनमार्क ने तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (GIM) 2024, चेन्नई, तमिलनाडु में स्थायी एनर्जी समाधान क्षेत्र में **भारत और डेनमार्क** के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल, "**ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया" (GFAI)** लॉन्च की है।

i.यह दोनों देशों को कार्बन तटस्थता की दिशा में संयुक्त ग्लोबल गोल को आगे बढ़ाने में भी सहायता करेगा।

ii.इस पहल का नेतृत्व भारत में **डेनिश दूतावास** और **डेनमार्क के महावाणिज्य दूतावास** द्वारा किया गया है।

GFAI के बारे में:

i.यह पहल ग्रीन फ्यूल्स क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जिसमें डेनिश उद्योगों और भारत में उनके समकक्षों के बीच नवाचार, सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देकर ग्रीन हाइड्रोजन शामिल है।

ii.भारत ने 2070 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

iii.डेनमार्क ग्लोबल क्लाइमेट परफॉरमेंस इंडेक्स (2024) में शीर्ष पर है और 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की राह पर है।

प्रमुख बिंदु:

i.इस पहल का उद्देश्य भारतीय और डेनिश दोनों क्षेत्रों के व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों और वित्तीय हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर भारत में सतत विकास को बढ़ावा देना है।

ii.डेनमार्क के नौ प्रमुख संगठनों ने संस्थापक सदस्यों के रूप में GFAI पहल का समर्थन करने का वादा किया है।

- 9 संगठन मार्सक, हल्दोर टोपसो, उमवेल्ट एनर्जी, मैश मेक्स, यूरोपियन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, नोवोजाइम्स, डैनफॉस, Brdr. क्रिस्टेंसेन और हाइड्रोजन डेनमार्क हैं ।

GFAI का सलाहकार समूह:

GFAI के सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में भारत हाइड्रोजन एलायंस, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT, मद्रास) में एनर्जी कंसोर्टियम, डेनिश एनर्जी एजेंसी और स्टेट ऑफ ग्रीन शामिल हैं।

पृष्ठभूमि:

i.GFAI को भारत और डेनमार्क के प्रधान मंत्री के बीच 2020 में हस्ताक्षरित ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (GSP) के तहत विकसित किया गया था।

ii.GSP मुख्य रूप से ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्टवाटर मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है।

- ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन विंड और सोलर एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है। यह किसी भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है।

अतिरिक्त जानकारी: मेर्स्क ने पूरे कारोबार में 2040 तक शुद्ध-शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है और ग्रीन हाइड्रोजन में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 2030 के लिए एक महत्वाकांक्षी अल्पकालिक लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

<u>डेनमार्क के बारे में:</u>

प्रधान मंत्री– मेटे फ्रेडरिकसेन

राजधानी– कोपेनहेगन

मुद्रा– डेनिश क्रोन

ULFA गुट ने भारत & असम सरकार के साथ निपटान का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

29 दिसंबर 2023 को, अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (**ULFA**) के गुट ने भारत और असम सरकार के साथ एक निपटान का ज्ञापन (शांति समझौते) पर हस्ताक्षर किए।

- ULFA के वार्ता समर्थक प्रतिनिधिमंडल के 29 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल (16 ULFA सदस्य, 13 नागरिक समाज के सदस्य) ने केंद्रीय मंत्री, अमित शाह, गृह मंत्रालय (MoHA) की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ULFA के बारे में:

i.ULFA, असम का सबसे पुराना विद्रोही समूह, बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) के अनिर्दिष्ट अप्रवासियों के खिलाफ आंदोलन के बाद अप्रैल 1979 में गठित किया गया था।

ii.2011 में, अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व वाले गुट द्वारा हिंसा छोड़ने और सरकार के साथ बिना शर्त बातचीत के लिए सहमत होने के बाद समूह 2 गुटों में विभाजित हो गया।

iii.वार्ता समर्थक गुट ने असम के स्वदेशी लोगों की भूमि के अधिकार सहित उनकी पहचान और संसाधनों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों की मांग की है।

REC लिमिटेड & RVNL ने RVNL इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को 35,000 करोड़ रुपये तक वित्तपोषित करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

REC लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) ने अगले 5 वर्षों में RVNL द्वारा निष्पादित की जाने वाली मल्टी-मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए **35,000 करोड़ रुपये** तक के वित्तपोषण के लिए **रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL)** के साथ एक समझौता ज्ञापन (**MoU**) पर हस्ताक्षर किए।

- इन प्रोजेक्ट्स में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब परियोजनाएं, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं और सड़क, बंदरगाह और मेट्रो परियोजनाएं शामिल होंगी जहां RVNL उद्यम कर रही है।

नोट: REC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) है, जबकि RVNL रेल मंत्रालय के तहत एक अनुसूची 'A' नवरत्न CPSE है।

हस्ताक्षरकर्ता: REC के निदेशक(वित्त) अजॉय चौधरी, REC; और RVNL के निदेशक (संचालन) राजेश प्रसाद ने MoU पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख लोगों:

V.K. देवांगन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD), REC लिमिटेड; संजीब कुमार, निदेशक (वित्त), RVNL; अनुपम बान, निदेशक (कार्मिक) RVNL और REC और RVNL के अन्य वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे।

प्रमुख बिंदु:

i.REC लिमिटेड विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक ऋण और वित्तीय समाधान प्रदान करता है, जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा (RE), इलेक्ट्रिक वाहन (EV), बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन शामिल हैं।

ii.REC लिमिटेड ने सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों आदि सहित गैर-विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विविधता लाई और स्टील और रिफाइनरी जैसे क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (E&M) कार्य किए।

- REC की पर्याप्त ऋण पुस्तिका 4,74,275 करोड़ रुपये से अधिक है।

iii.RVNL भारतीय रेलवे की लगभग 30% इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) PPP मॉडल के तहत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अग्रणी है।

iv.RVNL का प्राथमिक ध्यान रेलवे प्रोजेक्ट्स पर है, जिसमें सड़क, बंदरगाह, सिंचाई और मेट्रो प्रोजेक्ट्स का विस्तार शामिल है, जो अक्सर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं।

REC लिमिटेड के बारे में:

CMD– विवेक कुमार देवांगन

मुख्यालय– गुरुग्राम, हरियाणा

स्थापित– 1969

NHAI & NRSC ने भारत में नेशनल हाइवेज के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने भारत में विशाल नेशनल हाइवेज नेटवर्क के लिए **"ग्रीन कवर इंडेक्स"** विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए 3 साल के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (**ISRO**) के प्राथमिक केंद्रों में से एक **नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC)** के साथ समझौता ज्ञापन (**MoU**) पर हस्ताक्षर किए।

ग्रीन हाइवेज पॉलिसी:

मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज (MoRTH) और NHAI ने 2015 में ग्रीन हाइवेज पॉलिसी की शुरुआत के बाद से हाइवेज कोर्रिडोर्स के ग्रीनिंग को प्राथमिकता दी है।

वर्तमान में, वृक्षारोपण की निगरानी क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा साइट के दौरे पर आधारित है।

व्यापक अखिल भारतीय अनुमान:

i.हाई-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके, NRSC नेशनल हाइवेज के लिए 'ग्रीन कवर इंडेक्स' के रूप में संदर्भित ग्रीन कवर का एक व्यापक अखिल भारतीय आकलन करेगा।

- यह दृष्टिकोण न केवल इन-सीटू डेटा संग्रह को बढ़ाता है बल्कि NHAI द्वारा किए गए प्रदर्शन ऑडिट सहित वृक्षारोपण प्रबंधन और निगरानी को भी पूरक बनाता है।

ii.इस अभिनव दृष्टिकोण का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और जहां ग्रीन कवर अपर्याप्त है, वहां लक्षित हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करना है।

लाभ: यह नेशनल हाइवेज के किनारे ग्रीननेस्स के व्यापक स्तर के अनुमान उत्पन्न करने के लिए समय बचाने और लागत प्रभावी समाधान का वादा करता है।

क्षेत्र-वार ग्रीन कवर इंडेक्स प्राप्त करना:

i.परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य प्रारंभिक मूल्यांकन चक्र में नेशनल हाइवेज के लिए क्षेत्र-वार ग्रीन कवर इंडेक्स पर कब्जा करना है।

ii.बाद के वार्षिक चक्रों में नेशनल हाइवेज के लिए हरित आवरण के विकास पैटर्न का अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

iii.ग्रीन कवर इंडेक्स के निष्कर्ष विभिन्न नेशनल हाइवेज की तुलना और रैंकिंग को सक्षम करेंगे।

- यह जानकारी ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए समय पर और आवधिक हस्तक्षेपों का समर्थन करेगी।

व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए ग्रैन्युलर मेट्रिक्स:

नेशनल हाइवेज की प्रत्येक 1 किलोमीटर (km) लंबाई के लिए ग्रीन कवर का अनुमान लगाया जाएगा, जिससे व्यक्तिगत परियोजनाओं/पैकेजों के लिए भी ग्रैन्युलर मेट्रिक्स तैयार करने की अनुमति मिलेगी।

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) के बारे में:

1 सितंबर, 2008 से NRSC को ISRO के पूर्ण केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। इससे पहले, यह अंतरिक्ष विभाग (DOS) के तहत नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी (NRSA) नामक एक स्वायत्त निकाय था।

निदेशक– डॉ. प्रकाश चौहान

मुख्यालय– हैदराबाद, तेलंगाना

स्थापित- 1974

QCI & KVIC ने खादी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए; मेड-इन-इंडिया खादी लेबल पेश किया गया

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) और **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** ने खादी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, खादी के लिए मेड-इन-इंडिया लेबल पेश करने और खादी कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए अहमदाबाद (गुजरात) के कोचरब आश्रम में समझौता ज्ञापन **(MoU)** पर हस्ताक्षर किए।

KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार; और QCI के अध्यक्ष जक्सय शाह की उपस्थिति में MoU का आदान-प्रदान किया गया।

- MoU के अनुसार, QCI विभिन्न गतिविधियों में KVIC की सहायता करेगा, जिसमें उन्नत उत्पाद गुणवत्ता के लिए प्रशिक्षण, उत्पादकता में सुधार और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की विपणन क्षमता शामिल है।
- यह सहयोग खादी को 'मेड इन इंडिया' लेबल के रूप में एक नई पहचान देगा, और इसका उद्देश्य खादी उत्पादों को विश्व स्तर पर गुणवत्ता के प्रतीक के रूप में स्थापित करना, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि को बढ़ावा देना है।
- यह खादी कारीगरों को उन्नत कौशल और ज्ञान के साथ सशक्त बनाकर अधिक उत्पादकता और दक्षता के साथ रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा।

PFC ने 25,000 करोड़ रुपये की पावर प्रोजेक्ट्स के लिए गुजरात सरकार के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) ने पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गांधीनगर में गुजरात सरकार (GoG) के साथ 25,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

- PFC विद्युत मंत्रालय (MoP) के तहत एक अनुसूची-A महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) है।

उपस्थित प्रतिनिधि:

गुजरात के मुख्यमंत्री (CM) भूपेन्द्र पटेल की उपस्थिति में PFC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) परमिंदर चोपड़ा और GUVNL के जय प्रकाश शिवहरे (MD) ने MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

MoU के बारे में:

i.MoU के अनुसार, PFC GoG के स्वामित्व वाली फर्मों द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का समर्थन करता है

- गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (**GUVNL**)
- गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (**GSECL**)
- गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (**GETCO**)
- दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (**DGVCL**)
- मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (**MGVCL**)
- पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (**PGVCL**)
- उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (**UGVCL**)

ii.PFC इन संस्थाओं की पावर इंफ्रास्ट्रचर प्रोजेक्ट्स के विस्तार के लिए धन भी प्रदान करता है।

iii.MoU गुजरात में रोजगार सृजन भी करेगा।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) के बारे में:

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) बिजली क्षेत्र की एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (**NBFC**) है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) - परमिंदर चोपड़ा

मुख्यालय – नई दिल्ली, दिल्ली

स्थापना – 1986

गुजरात के बारे में:

मुख्यमंत्री - भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल

राज्यपाल – आचार्य देवव्रत

हवाई अड्डे - श्यामजी कृष्ण वर्मा भुज हवाई अड्डा, पोरबंदर हवाई अड्डा

UNESCO विश्व धरोहर स्थल - चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क, रानी-की-वाव (रानी की बावड़ी)

MoD ने मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए ज्यूपिटर वैगन्स लिमिटेड & BEML के साथ 802 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय (**MoD**) ने स्वदेशी मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए **802 करोड़ रुपये** के **2 अनुबंध** पर हस्ताक्षर किए हैं। **697** बोगी ओपन मिलिट्री (**BOM**) वैगन्स की खरीद के लिए M/S **ज्यूपिटर वैगन्स लिमिटेड** के साथ **473 करोड़ रुपये** का **पहला अनुबंध** किया गया था।

- **56** मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट (**MMME**) मार्क II की खरीद के लिए M/S BEML लिमिटेड (पूर्व में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) के साथ **329.87 करोड़ रुपये** के दूसरे अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- खरीददारी भारतीय खरीद-IDDM (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणी के तहत की गई थी।

नोट:

BOM वैगन्स और MMME मार्क II दोनों का उत्पादन स्वदेशी निर्माताओं के और उप-प्रणालियों का उपयोग करके किया जाएगा।

बोगी ओपन मिलिट्री (BOM) वैगन्स के बारे में:

i.रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (RDSO) द्वारा डिजाइन किए गए BOM वैगन, भारतीय सेना द्वारा सेना इकाइयों को संगठित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेषज्ञ वैगन हैं।

ii.BOM वैगन्स का उपयोग लाइट व्हीकल्स, आर्टिलरी गन, BMP, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट आदि को उनके शांतिकालीन स्थानों से परिचालन क्षेत्रों तक ले जाने के लिए किया जाता है।

- BMP का मतलब Boyevaya Mashina Pekhoty है, जो एक रूसी वाक्यांश है जिसका अनुवाद "फाइटिंग व्हीकल ऑफ़ इन्फेंट्री" है।

iii.क्रिटिकल रोलिंग स्टॉक संघर्ष के दौरान परिचालन क्षेत्रों में इकाइयों और इक्विपमेंट की तीव्र और एक साथ तैनाती सुनिश्चित करता है और सैन्य अभ्यास और यूनिट स्थानांतरण के लिए शांतिकाल के हलचलों का समर्थन करता है।

MMME-मार्क II के बारे में:

i.संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय (**UNODA**) द्वारा कुछ पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन' के संशोधित प्रोटोकॉल-II के तहत सभी बारूदी सुरंगों को चिह्नित करना एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।

ii.MMME को स्टोरों के पूर्ण भार के साथ क्रॉस-कंट्री संचालित करने और न्यूनतम समय और जनशक्ति रोजगार के साथ खदान क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

iii.यह इक्विपमेंट उन्नत यांत्रिक और विद्युत प्रणालियों का लाभ उठाने वाले इन-सर्विस हाई मोबिलिटी व्हीकल पर आधारित है।

- इस एकीकरण से ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंगों को चिह्नित करने का समय कम हो जाएगा और भारतीय सेना की समग्र परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी।

भारतीय रेलवे ने ग्रीन इनिशिएटिव्स को सुविधाजनक बनाने के लिए CII के साथ तीसरे MoU पर हस्ताक्षर किए

4 जनवरी 2024 को, **भारतीय रेलवे (IR)** और भारतीय उद्योग परिसंघ (**CII**) ने एनर्जी और पानी की खपत को कम करने और ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने के लिए समझौता ज्ञापन (**MoU**) पर हस्ताक्षर किए हैं।

- 2016 से लगातार तीसरी बार MoU का नवीनीकरण किया गया।
- CII-ग्रीन बिजनेस सेंटर (GBC) के साथ इस नवीनीकृत MoU का लक्ष्य 2030 तक IR के नेट जीरो कार्बन एम्मिशन के लक्ष्य को हासिल करना है।

हस्ताक्षरकर्ता:

रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यकारी निदेशक/मैकेनिकल इंजीनियरिंग (EnHM & प्रोजेक्ट) शैलेन्द्र सिंह और CII की उप महानिदेशक सीमा अरोड़ा के बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जया वर्मा सिन्हा की उपस्थिति में MoU पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान किया गया।

MoU के तहत प्रमुख इनिशिएटिव्स:

इस नवीनीकृत MoU के तहत IR और CII संयुक्त रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेंगे:

- नई/प्रासंगिक प्रौद्योगिकियाँ लाना और उनका कार्यान्वयन।
- कार्यशालाओं/उत्पादन इकाइयों (PU) के लिए ISO 50001 सर्टिफिकेशन (एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन) प्राप्त करने में सहायता।
- नेट-जीरो एनर्जी रेलवे स्टेशन ढांचे का विकास।
- पूरे वर्ष ग्रीन इनिशिएटिव्स में हुई प्रगति पर प्रकाश डालने वाले एक सूचना डैशबोर्ड का निर्माण।

पिछले MoU:

i.CII जुलाई 2016 से IR पर ग्रीन इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए IR के साथ एक प्रमुख भागीदार रहा है।

ii.पहला MoU 2016 में 3 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। इसकी समाप्ति के बाद, 2019 में अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए दूसरे MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के बारे में:

महानिदेशक– चंद्रजीत बनर्जी
मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली
स्थापित– 1895

विटोल और GAIL ने भारत में दीर्घकालिक LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (**MoPNG**) के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (**CPSE**) GAIL (इंडिया) लिमिटेड ने लगभग 10 वर्षों की अवधि के लिए **2026** से प्रभावी भारत में प्रति वर्ष लगभग एक मिलियन मीट्रिक टन LNG की आपूर्ति के लिए सिंगापुर स्थित **विटोल एशिया Pte लिमिटेड** के साथ दीर्घकालिक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (**LNG**) सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं।

- इस सौदे के तहत, विटोल अपने वैश्विक LNG पोर्टफोलियो से अखिल भारतीय आधार पर भारत में GAIL को LNG वितरित करेगा।

GAIL (इंडिया) लिमिटेड के बारे में:

अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक (CMD) – संदीप कुमार गुप्ता
मुख्यालय – नई दिल्ली, दिल्ली
स्थापना – 1984

कोल इंडिया लिमिटेड ने बहु कौशल विकास संस्थानकी स्थापना के लिए NSDC के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

कोल इंडिया लिमिटेड (**CIL**) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (**NSDC**) ने CIL की प्रत्येक सहायक कंपनियों में बहु कौशल विकास संस्थान(**MSDI**) स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (**MoU**) पर हस्ताक्षर किए हैं।

नोट: CIL मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) है और **NSDC मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस** द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के रूप में स्थापित एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है।

चरणबद्ध कार्यान्वयन:

MoU के अनुसार, पहले चरण में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL), नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) से शुरू होने वाली CIL की प्रत्येक सहायक कंपनियों में MSDI स्थापित किए जाएंगे।

- शेष सहायक कंपनियों को अगले चरण में कवर किया जाएगा।

मौजूदा बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण:

CIL सहायक कंपनियों के भीतर मौजूदा बुनियादी ढांचे को MSDI के रूप में काम करने के लिए पुनर्निर्मित और विकसित किया जाएगा। परियोजना में शामिल हैं:

- मौजूदा बुनियादी ढांचे को MSDI के रूप में पुन: उपयोग करने के लिए एकमुश्त पूंजीगत व्यय (कैपेक्स);
- वार्षिक आवर्ती और परियोजना निगरानी इकाई (PMU) खर्च।

नोट: यह पहल कौशल विकास को बढ़ावा देने और कोल-असर वाले क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार पैदा करने की CIL की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

CIL ने झारखंड के 11 जिलों में शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए EdCIL के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

CIL ने **झारखंड के 11 जिलों** में शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए **EdCIL (इंडिया) लिमिटेड** के साथ एक **MoU** पर हस्ताक्षर किए। MoU पर **CIL** की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (**CSR**) **पहल** के एक भाग के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे।

- यह परियोजना CIL की 3 सहायक कंपनियों ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के खनन क्षेत्रों वाले झारखंड के 11 जिलों में लागू की जाएगी।
- परियोजना की अनुमानित लागत 27.08 करोड़ रुपये है और इसे 3 वर्षों में लागू किया जाएगा।

उद्देश्य:

नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप इस पहल का उद्देश्य झारखंड में CIL की सहायक कंपनियों ECL, BCCL और CCL के कोल खनन क्षेत्रों के आसपास के स्कूलों में सीखने के परिणामों में सुधार करके समृद्ध शैक्षिक सामग्री के साथ छात्रों को सशक्त बनाना है।

मुख्य परियोजना विवरण:

i.इस परियोजना के एक भाग के रूप में, प्रत्येक चिन्हित स्कूल में एक स्मार्ट कक्षा और एक सूचना & संचार प्रौद्योगिकी (ICT) प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।

ii.परियोजना में शिक्षक प्रशिक्षण और स्थापित उपकरणों के 3 साल के रखरखाव के प्रावधान भी शामिल हैं।

प्रमुख लोग:

MoU पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अतिरिक्त सचिव रूपिंदर बराड़; विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक और औद्योगिक संबंध), CIL और मनोज कुमार, अध्यक्ष और प्रबंध (CMD) निदेशक, EdCIL (इंडिया) लिमिटेड की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम अन्वेषण और खनन परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (**KABIL**) ने 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स का पता लगाने और विकसित करने के लिए **अर्जेंटीना** के कैटामार्का में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम **Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE)** के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- यह समझौता लगभग 200 करोड़ रुपये और यह भारत सरकार के **स्वामित्व वाले उद्यम** द्वारा **पहली** लिथियम अन्वेषण और खनन परियोजना है।
- 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक नामतः कॉर्टेडेरा-I, कॉर्टेडेरा-VII, कॉर्टेडेरा-VIII, कैटियो-2022-01810132 और कॉर्टेडेरा-VI हैं।

प्रमुख बिंदुः

i.KABIL लगभग 15,703 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स की अन्वेषणऔर विकास शुरू करेगा।

ii.KABIL कैटामार्का, अर्जेंटीना में एक शाखा कार्यालय स्थापित करने की भी योजना बना रहा है।

iii.इस समझौते के साथ, KABIL ने 5 मिनरल ब्लॉक्स से लिथियम के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अन्वेषण और विशिष्टता अधिकार प्राप्त कर लिया है।

iv.समझौता KABIL को मूल्यांकन, संभावना और अन्वेषण करने की अनुमति देगा।

- लिथियम मिनरल्स की बाद की खोज पर, वाणिज्यिक उत्पादन के लिए शोषण के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं।

v.इसका उद्देश्य ब्राइन-टाइप लिथियम अन्वेषण, शोषण और निष्कर्षण के लिए तकनीकी और परिचालन अनुभव लाना है।

प्रमुख लोगः

i.हस्ताक्षर समारोह में वस्तुतः निम्नलिखित ने भाग लिया:

- केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, खान मंत्रालय, भारत सरकार;
- V. L. कांथा राव, सचिव, खान मंत्रालय;
- श्रीधर पात्रा, KABIL के अध्यक्ष और NALCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD)।

ii.इस समझौते पर कैटामार्का Lic के गवर्नर राउल जलील; कैटामार्का के वाईस गवर्नर, Eng. रुबेन डूसो; और खान मंत्री कैटामार्का, H. E. मार्सेलो मुरुआ और अर्जेंटीना में भारत के राजदूत, H. E. दिनेश भाटिया की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

ध्यान देने योग्य बातें:

i.अर्जेंटीना दुनिया के कुल लिथियम संसाधनों के आधे से अधिक के साथ चिली और बोलीविया के साथ "लिथियम ट्राईएंगल" का हिस्सा है।

ii.अर्जेंटीना को निम्नलिखित का गौरव प्राप्त है:

- दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लिथियम संसाधन; तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार; और चौथा सबसे बड़ा उत्पादन।

खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) के बारे में:

अध्यक्ष– श्रीधर पात्रा

CEO– सदाशिव सामंतराय

मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली

KABIL को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2019 में शामिल किया गया था।

- KABIL खान मंत्रालय, भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL), और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (MECL) का 40:30:30 के अनुपात में एक संयुक्त उद्यम (JV) है।

ओडिशा सरकार ने एंथ्रेक्स & ENT टीकों के उत्पादन के लिए नई GMP सुविधा स्थापित करने के लिए NDDB के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

ओडिशा सरकार के **मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास (ARD) विभाग** ने **गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP)** सुविधा स्थापित करने के लिए **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)** के साथ एक समझौता ज्ञापन (**MoU**) पर हस्ताक्षर किए।

- GMP सुविधा **बरहामपुर** में ओडिशा जैविक उत्पाद संस्थान (**OBPI**) की सैटेलाइट यूनिट में **एंथ्रेक्स** और **एंटरोटॉक्सिमिया (ENT) टीकों** के **उत्पादन** के लिए है।

परियोजना का अनुमान:

i.इन टीकों के उत्पादन के लिए परियोजना में 52.20 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।
ii.प्रयोगशाला का निर्माण कार्य 36 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

वर्तमान उत्पादन स्थिति:

बरहामपुर में OBPI की मौजूदा सैटेलाइट यूनिट वर्तमान में उत्पादन करती है:

- एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन (ASV) की 22 लाख खुराक; और
- पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके सालाना ENT वैक्सीन (ENTV) की 14 लाख खुराकें।

प्रौद्योगिकी का उन्नयन:

GMP प्रयोगशाला की स्थापना बेहतर वैक्सीन गुणवत्ता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानदंडों और भारत के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 का पालन करेगी।

- एक बार चालू होने पर, यह क्रमशः ENTV की 2 करोड़ खुराक और ASV टीकों की 50 लाख खुराक का उत्पादन करेगा।

NDDB की भूमिका:

i.NDDB GMP यूनिट सेटअप के लिए परामर्श और पर्यवेक्षी सेवाएं प्रदान करेगा।
ii.NDDB की भागीदारी में प्लांट के ट्रायल रन और अंतिम कमीशनिंग की देखरेख शामिल है।

प्रमुख बिंदु:

यह परियोजना ओडिशा में पशुधन और मुर्गीपालन के लिए स्वास्थ्य देखभाल और रोग प्रबंधन में बदलाव के लिए **5T पहल** के तहत शुरू की गई है।

- 5T पहल ओडिशा में एक शासन मॉडल है जो **टी**मवर्क, **ट्रां**सपेरेंसी, **टे**क्नोलॉजी, **टा**इम और **ट्रां**सफॉर्मेशन के लिए है।

ओडिशा के बारे में:

मुख्यमंत्री– नवीन पटनायक
राज्यपाल– रघुबर दास
टाइगर रिजर्व- सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व
वन्यजीव अभ्यारण्य- सतकोसिया गॉर्ज अभ्यारण्य (अंगुल) और नंदनकानन अभ्यारण्य (भुवनेश्वर)

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बारे में:

अध्यक्ष– डॉ. मीनेश C शाह
मुख्यालय– आनंद, गुजरात
स्थापित-1965 में

ICG & SAIL ने स्वदेशी सामग्री जहाज बढ़ाने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

भारतीय तट रक्षक (ICG) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने नई दिल्ली, दिल्ली में ICG के जहाज में स्वदेशी सामग्री (IC) को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (**MoU**) पर हस्ताक्षर किए हैं।

- MoU के अनुसार, SAIL ICG जहाजों के लिए भारतीय शिपयार्डों को स्वदेशी मरीन-ग्रेड स्टील की आपूर्ति करेगा।
- भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक (DGICG) **राकेश पाल** की उपस्थिति में MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के बारे में:

SAIL एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (**CPSE**) है जो इस्पात मंत्रालय (MoS) के अधीन कार्य करता है।
अध्यक्ष-अमरेंदु प्रकाश
मुख्यालय – नई दिल्ली, दिल्ली
स्थापना – 1973

DEPWD और NHRDN ने दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय **(MoSJE)** के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग **(DEPWD)** और नेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नेटवर्क **(NHRDN)** ने विकलांग व्यक्तियों **(दिव्यांगजन)** के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन **(MoU)** पर हस्ताक्षर किए हैं।

- पूरे भारत में ह्यूमन रिसोर्सेज (HR) पेशेवरों से जुड़कर DEPWD के डिजिटल पोर्टल **PM-DAKSH-DEPWD** के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

गूगल पे इंडिया ने वैश्विक स्तर पर UPI का विस्तार करने के लिए NPCI इंटरनेशनल के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

17 जनवरी, 2024 को, **गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज (P) लिमिटेड** (गूगल पे इंडिया) और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच वैश्विक स्तर पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का विस्तार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन **(MoU)** पर हस्ताक्षर किए गए।

- इस MoU के तीन मुख्य लक्ष्य विश्व स्तर पर भारतीय यात्रियों के लिए UPI पेमेंट्स का विस्तार करना, अन्य देशों में UPI जैसी प्रणालियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करना और UPI बुनियादी ढांचे का उपयोग करके सीमा पार प्रेषण को सरल बनाना हैं।

प्रमुख बिंदु:

i.यह MoU अन्य देशों में UPI जैसी प्रणाली स्थापित करके और विदेशी व्यापारियों को भारतीय ग्राहकों तक पहुंच प्रदान करके UPI की वैश्विक पहुंच को बढ़ाता है।
ii.भारतीय यात्री अब इंटरनेशनल ट्रांसेक्शन्स के लिए केवल विदेशी मुद्रा और/या क्रेडिट या विदेशी मुद्रा कार्ड पर निर्भर रहने के बजाय वैश्विक स्तर पर डिजिटल पेमेंट्स के लिए गूगल पे जैसे UPI-संचालित ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
iii.यह पारंपरिक धन हस्तांतरण चैनलों पर निर्भरता को कम करके सीमा पार प्रेषण को भी सरल बनाता है।
iv.30 अप्रैल, 2023 तक, इन देशों: सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), और यूनाइटेड किंगडम (UK) के इंटरनेशनल मोबाइल नंबर UPI ट्रांसेक्शन्स सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

- यह सुविधा उन अनिवासी खातों को UPI के साथ ट्रांसेक्शन्स करने की अनुमति देती है जिनके पास इंटरनेशनल मोबाइल नंबर हैं।

आधिकारिक अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें

NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) के बारे में:

CEO-रितेश शुक्ला

मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापना- 2020

IFSC GIFT सिटी ने ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म के लिए IGX, GSPC के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

17 जनवरी, 2024 को, गुजरात के गांधीनगर में GIFT सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) ने ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म स्थापित करने के लिए **इंडियन गैस एक्सचेंज** (IGX) और **गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन** (GSPC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। MoU पर 10-12 जनवरी, 2024 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।

- इस पर मुख्यमंत्री (CM) भूपेन्द्र पटेल, IGX के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) **राजेश K मेदीरत्ता**, GSPC के MD **मिलिंद तोरावणे** और GIFT सिटी के IFSC विभाग प्रमुख **संदीप शाह** की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

सहयोग के तहत क्या किया जाएगा?

ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म यानी ग्लोबल हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स की शुरूआत होगी, जो जर्मनी के लीपज़िग में यूरोपीयन एनर्जी एक्सचेंज (EEX) द्वारा हाइड्रिक्स के बाद ग्लोबली पर अपनी तरह का दूसरा होगा, जो दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स है।

- ग्लोबल हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट के लिए मूल्य खोज और मार्केट अंतर्दृष्टि के लिए प्रमुख बेंचमार्क के रूप में कार्य करेगा।
- इससे पारदर्शिता में सुधार करने, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और ग्लोबली पर ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट के विस्तार में मदद मिलेगी।

प्रमुख बिंदु:

i.GIFT IFSC का लक्ष्य इंटरनेशनल सिक्योरिटीज और कमोडिटीज ट्रेडिंग को बढ़ावा देने और एक सस्टेनेबल इंटरनेशनल फाइनेंसियल हब बनाने के माध्यम से ग्लोबल कमोडिटी कीमतें निर्धारित करने में नेतृत्व करना है।

- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि GIFT सिटी के विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को भारत में IFSC के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह बैंकिंग, बीमा, पूंजी मार्केट, परिसंपत्ति प्रबंधन और फिनटेक जैसे परिचालन क्षेत्रों की मेजबानी करता है।

ii.IGX प्राकृतिक गैस की भौतिक डिलीवरी के लिए भारत का पहला स्वचालित राष्ट्रीय स्तर का गैस एक्सचेंज है।

iii.भारत सरकार (GoI) ने 2030 तक भारत की एनर्जी बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.5% से बढ़ाकर 15% करने का नीतिगत लक्ष्य निर्धारित किया है।

इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) के बारे में:

यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) के नियामक ढांचे के तहत संचालित होता है।

प्रबंध निदेशक & CEO– राजेश कुमार मेदीरत्ता

मुख्यालय– नोएडा, उत्तर प्रदेश (UP)

स्थापना- 2020

AFMS & AIIMS ने वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय **(MoD)** के तहत सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा **(AFMS)** और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान **(AIIMS)**, नई दिल्ली, दिल्ली ने बहु-विषयक वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों को संबोधित करते हुए पारस्परिक हित, संयुक्त अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन **(MoU)** पर हस्ताक्षर किए।

- MoU पर AFMS के महानिदेशक (DG) लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और AIIMS के निदेशक प्रोफेसर M श्रीनिवास ने हस्ताक्षर किए।

MoU के बारे में:

i.MoU का उद्देश्य संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, सामान्य शैक्षिक गतिविधियों और एक संकाय विनिमय कार्यक्रम का संचालन करना है।

ii. MoU में संभावित सहयोग का पता लगाने के लिए पांच सदस्यीय सहयोग बोर्ड बनाने का भी इरादा है।

IREDA & IOB ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के सह-ऋण के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड **(IREDA)** और इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने पूरे भारत में **रिन्यूएबल एनर्जी** प्रोजेक्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए को-लेंडिंग और लोन सिंडिकेशन के लिए एक प्लेटफार्म स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (**MoU**) पर हस्ताक्षर किए।

- MoU में सभी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए सह-ऋण और सह-उत्पत्ति समर्थन के प्रावधान शामिल हैं।
- MoU पर नई दिल्ली, दिल्ली में IREDA के बिजनेस सेंटर में हस्ताक्षर किए गए।

नोट: IREDA मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी - I) उद्यम है।

उद्देश्य:

साझेदारी का उद्देश्य IREDA उधारकर्ताओं के लिए लोन सिंडिकेशन और अंडरराइटिंग प्रोसेसेज और ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट (TRA) के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है।

- स्थिरता के उद्देश्य से, यह सहयोग IREDA उधारों के लिए **3-4** साल की अवधि में निश्चित ब्याज दरों की दिशा में काम करता है।

हस्ताक्षरकर्ता:

MoU पर IREDA के महाप्रबंधक डॉ. RC शर्मा और IOB के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अजय कुमार श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर किए।

साझेदारी के बारे में:

i.इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्थिरता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है।

ii.यह सहयोग 2030 तक 500 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म-आधारित बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है।

iii.यह सहयोग बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों के साथ IREDA की समान सफल साझेदारी को जोड़ता है।

इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के बारे में:

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD)- प्रदीप कुमार दास

मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली

यह एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जिसे 1987 में एक नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।

आदर्श वाक्य - एनर्जी फॉर एवर

ICAI ने 'विज़न 2049' विकसित करने के लिए IIM अहमदाबाद के साथ सहयोग किया

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया **(ICAI)** की रणनीति परिप्रेक्ष्य योजना और निगरानी समिति ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) अहमदाबाद (गुजरात) के साथ साझेदारी में **ICAI विजन 2049** तैयार करने का कार्य शुरू किया है।

ICAI विजन 2049 के बारे में:

i.इसका उद्देश्य ICAI को अकाउंटेंसी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नेता बनाना है।
ii.चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आर्थिक प्रगति के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे।
iii.ICAI 2049 में अपने अस्तित्व की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा।

डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर सहयोग के लिए MeitY ने क्यूबा के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

19 जनवरी 2024 को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**), भारत सरकार ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्यूबा गणराज्य के संचार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (**MoU**) पर हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षरकर्ता: MoU पर S कृष्णन, सचिव, MeitY (भारत) और महामहिम श्री विल्फ्रेडो गोंजालेज विडाल, प्रथम उप संचार मंत्री (क्यूबा) ने नई दिल्ली, दिल्ली में हस्ताक्षर किए।

MoU के बारे में:

i.MoU भारत और क्यूबा के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को पारस्परिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और अन्य सहयोगी गतिविधियों के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन (INDIA STACK) को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
ii.इस MoU के तहत, भारत क्यूबा में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निर्बाध रूप से अपनाने की सुविधा के लिए डिजिटल परिवर्तन पर विकास साझेदारी का निर्माण करके क्यूबा के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इंडिया स्टैक के बारे में:

i.इंडिया स्टैक वह नाम है जिसका उपयोग अलग-अलग प्रौद्योगिकी उत्पादों और रूपरेखाओं के संग्रह का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
ii.यह ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक सेट है जिसका उद्देश्य जनसंख्या पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करना है।

क्यूबा के बारे में:

राजधानी– हवाना
प्रधान मंत्री– मैनुअल मारेरो क्रूज़
राष्ट्रपति– मिगुएल मारियो DÍAZ-CANEL बरमूडेज़
मुद्रा– क्यूबन पेसो (CUP)

भारत के ACME और जापान के IHI कॉर्पोरेशन ने भारत से जापान को ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

23 जनवरी, 2024 को, भारत के ACME ग्रुप (उर्फ ACME क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड) और जापान के IHI कॉरपोरेशन ने दीर्घकालिक आधार पर ओडिशा से 0.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) **ग्रीन अमोनिया** की आपूर्ति के लिए एक टर्म शीट समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- यह समझौता वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इसके जीवनचक्र के बराबर 54 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की भरपाई करेगा।

हस्ताक्षरकर्ता:

इस टर्म शीट पर ACME के संस्थापक और अध्यक्ष **मनोज उपाध्याय** और IHI कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) **हिरोशी आइड** ने केंद्रीय मंत्री राज कुमार सिंह, नवीन & नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), सचिव MNRE भूपिंदर सिंह भल्ला और भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्रमुख बिंदु:

i.यह समझौता ओडिशा में ACME की गोपालपुर परियोजना में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन दर्शाता है, जिसका लक्ष्य चरणबद्ध कार्यान्वयन में 1.2 MMTPA क्षमता है। प्रारंभिक उत्पादन 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है।

ii.यह दुनिया में इस पैमाने के ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के पहले समझौतों में से एक है।

- परियोजना की कुल लागत लगभग **5 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है।

iii.यह समझौता भारत के **नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन** के साथ-साथ **जापान की नेट ज़ीरो कमिटमेंट** दोनों में योगदान देगा।

ACME ग्रुप (ACME क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड) के बारे में:

अध्यक्ष & MD-मनोज उपाध्याय

मुख्यालय–गुरुग्राम, हरियाणा

MoD ने 14 FPV की खरीद के लिए MDL के साथ 1070 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय **(MoD)** ने भारतीय तट रक्षक **(ICG)** के लिए **14** फास्ट पेट्रोल वेसल्स **(FPV)** के अधिग्रहण के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL - MoD के तहत कार्यरत) के साथ **1070 करोड़ रुपये** के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

अनुबंध के बारे में:

i.यह अनुबंध भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित **(IDDM)** श्रेणी के तहत किया गया था।

- FPV को MDL मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है।

ii.सभी FPV ICG को तिरसठ महीने में वितरित कर दिए जाएंगे।

iii.अनुबंध का उद्देश्य सहायक उद्योगों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम **(MSME)** क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना भी है।

FPV के बारे में:

i.FPV कई उच्च तकनीक उन्नत सुविधाओं और उपकरणों के साथ आते हैं।

ii.वेसल्स बहुउद्देशीय ड्रोन, वायरलेस रूप से नियंत्रित रिमोट जल बचाव शिल्प लाइफबॉय और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) क्षमता आदि से लैस होंगे।

iii.ये वेसल्स मत्स्य संरक्षण और निगरानी, नियंत्रण और निगरानी, तस्करी विरोधी अभियान और खोज और बचाव अभियान जैसी गतिविधियां करते हैं।

iv.वे संकटग्रस्त जहाजों/शिल्प को खींचने की क्षमता, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया संचालन और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में भी सहायता प्रदान करते हैं।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) के बारे में:

MDL कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत MoD के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) – संजीव सिंघल

मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
स्थापना – 1934
रक्षा मंत्रालय के बारे में:
केंद्रीय मंत्री - राज नाथ सिंह (निर्वाचन क्षेत्र: लखनऊ, उत्तर प्रदेश)
राज्य मंत्री (MoS) – अजय भट्ट (निर्वाचन क्षेत्र: नैनीताल-उधमसिंह नगर, उत्तराखंड)

MoRD & लेडी इरविन कॉलेज, दिल्ली ने ROSHNI-CWCSA के लिए 5-वर्षीय MoU का नवीनीकरण किया

23 जनवरी 2024 को, दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (**DAY–NRLM**), ग्रामीण विकास मंत्रालय (**MoRD**), और **लेडी इरविन कॉलेज**, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली, दिल्ली में ROSHNI– महिला सामूहिक नेतृत्व वाला सामाजिक कार्य केंद्र (CWCSA) के लिए 5 साल के समझौता ज्ञापन (MoU) का नवीनीकरण किया।
साझेदारी का उद्देश्य महिलाओं के लिए पोषण, लैंगिक समानता और आजीविका को मजबूत करना है।

MoU के बारे में:

i.इस MoU की 5 साल की अवधि के दौरान, MoRD ग्रामीण समुदायों के लिए खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और WASH (FNHW) के परिणामों को बढ़ाने के लिए ROSHNI-CWCSA के साथ सहयोग करेगा।
ii.इस साझेदारी का उद्देश्य FNHW और लिंग हस्तक्षेप के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRP) की क्षमता निर्माण को बढ़ाना भी है।
नोट:

- WASH का मतलब जल, सफाई और स्वच्छता है।
- DAY-NRLM, 2011 में लॉन्च किया गया, MoRD द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है।

ROSHNI-CWCSA:

i.यह तकनीकी और वित्तीय रूप से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (**UNICEF**) भारत द्वारा समर्थित है।
ii.लेडी इरविन कॉलेज में विकास संचार और विस्तार विभाग में स्थित, ROSHNI-CWCSA राष्ट्रीय स्तर पर DAY-NRLM के लिए एक तकनीकी और ज्ञान प्रबंधन सहायता इकाई के रूप में कार्य करता है।
iii.ROSHNI पूरे भारत में 9.96 करोड़ स्वयं सहायता ग्रुप (SHG) सदस्यों और उनके परिवारों के लिए FNHW परिणामों को बेहतर बनाने के लिए DAY-NRLM की सहायता करती है।

- इसका मिशन कुपोषण, डिजीज और गरीबी से जुड़े जेब से खर्च के चक्र को तोड़ना है।

iv.FNHW हस्तक्षेपों का एकीकरण SHG और उनके संघों में 1.2 लाख से अधिक प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के बारे में:
केंद्रीय मंत्री– गिरिराज सिंह (निर्वाचन क्षेत्र: बेगुसराय, बिहार)
राज्य मंत्री (MoS)- फग्गन सिंह कुलस्ते (निर्वाचन क्षेत्र: मंडला, मध्य प्रदेश); साध्वी निरंजन ज्योति (निर्वाचन क्षेत्र: फ़तेहपुर, उत्तर प्रदेश)

मध्य प्रदेश & राजस्थान और MoJS ने मॉडिफाइड PKC-ERCP लिंक प्रोजेक्ट पर MoU पर हस्ताक्षर किए

मध्य प्रदेश (MP), राजस्थान और जल शक्ति मंत्रालय (MoJS), भारत सरकार (GoI) ने "मॉडिफाइड PKC-ERCP" **(मॉडिफाइड पार्वती-कालीसिंध-चंबल विथ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट)** लिंक प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रमुख लोगों:

MoU हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मोहन यादव (MP के मुख्यमंत्री), श्रीराम वेदिरे, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर टास्क फोर्स के अध्यक्ष और भजन लाल शर्मा (राजस्थान के मुख्यमंत्री) ने भाग लिया।

मॉडिफाइड PKC-ERCP लिंक प्रोजेक्ट के लाभ:

i.मॉडिफाइड PKC-ERCP लिंक प्रोजेक्ट ईस्टर्न राजस्थान, मालवा और मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्रों के **13 जिलों** में पीने और औद्योगिक पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती है।

- ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर हैं।

ii.यह दोनों राज्यों में से प्रत्येक में 2.8 लाख हेक्टेयर (या अधिक) (कुल 5.6 लाख हेक्टेयर या अधिक) को सिंचाई प्रदान करेगा, साथ ही रास्ते में टैंकों की पूर्ति भी करेगा।

प्रोजेक्ट में किये जाने वाले कार्य:

i.मॉडिफाइड PKC-ERCP लिंक प्रोजेक्ट के लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की तैयारी है; उसके बाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश और GoI के बीच एक समझौते का ज्ञापन (MoA) को अंतिम रूप दिया जाएगा।

ii. MoA में निम्नलिखित: लिंक प्रोजेक्ट के काम का दायरा, पानी का बंटवारा, पानी का आदान-प्रदान, लागत & लाभ का बंटवारा, कार्यान्वयन तंत्र, और चंबल बेसिन में पानी के प्रबंधन और नियंत्रण की व्यवस्था का विवरण दिया गया है।

PKC & ERCP प्रोजेक्ट्स के विलय की यात्रा:

i.राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के तहत पार्वती-कालीसिंध-चंबल (**PKC**) लिंक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट (FR) फरवरी 2004 में तैयार की गई थी।

ii.राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर, 2017 में 37,247.12 करोड़ रुपये (2014 मूल्य स्तर पर) की अनुमानित लागत के साथ **ERCP** की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) प्रस्तुत की गई थी।

iii.ERCP शुरू नहीं हो पाई क्योंकि यह इंटर-स्टेट रिवर्स पर प्रोजेक्ट्स के मानदंडों से मेल खाने में विफल रही।

iv.PKC लिंक प्रोजेक्ट को ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) के साथ विलय करने पर विभिन्न चर्चाएं करने के बाद। 'मॉडिफाइड PKC-ERCP' लिंक प्रोजेक्ट को अंततः दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में स्पेशल कमिटी फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स (SCILR) की 20वीं बैठक में मंजूरी मिल गई।

- इसे भारत में प्राथमिकता वाली रिवर लिंक प्रोजेक्ट्स में से एक घोषित किया गया था।

v.मॉडिफाइड PKC-ERCP लिंक प्रोजेक्ट GoI के इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स (ILR) कार्यक्रम की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के तहत दूसरी प्रोजेक्ट है।

- केन-बेतवा ILR प्रोजेक्ट NPP के तहत पहली प्रोजेक्ट है।

लिंक की जाने वाली रिवर्स के बारे में:

i.चंबल रिवर तीन अलग-अलग राज्यों: मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह M.P. के इंदौर जिले में महू के पास विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

ii.पार्वती रिवर M.P. के सीहोर जिले में आस्था के पास विंध्यांचल पर्वतमाला से निकलती है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है।

iii.कालीसिंध रिवर चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह M.P. के देवास जिले में बागली गाँव के पास से निकलती है और राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी में मिलती है।

<u>राजस्थान के बारे में:</u>

मुख्यमंत्री - भजनलाल शर्मा

राज्यपाल– कलराज मिश्र

वन्यजीव अभ्यारण्य- जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य

नृत्य - घूमर नृत्य, गैर, चरी नृत्य

NSRCEL IIM-B और SIDBI ने स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलेरेटर फंड लॉन्च किया

बेंगलुरु, कर्नाटक में भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर **(IIMB)** में नादाथुर S राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग **(NSRCEL)**, जिसे 2000 में स्थापित किया गया था, ने भारत में प्रौद्योगिकी-उन्मुख स्टार्टअप के लिए प्री-सीड फंड सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (**SIDBI**) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

i.NSRCEL पिछले दो दशकों से भारत में शुरुआती चरण के उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और अपने प्रत्यक्ष निवेश से 1600 स्टार्टअप शुरू कर रहा है।

ii.SIDBI ने स्वास्थ्य सेवा, रक्षा नवाचार, ग्रामीण प्रभाव और अनुसंधान & विकास (R&D) जैसे कई क्षेत्रों में तकनीकी स्टार्टअप की शुरुआती फंडिंग के लिए विभिन्न भारतीय इनक्यूबेटरों के साथ साझेदारी की है।

- SIDBI, 1990 में गठित, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है।
- SIDBI के अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक (MD) श्री शिवसुब्रमण्यम रमन हैं।

COMMITTEES & MEETINGS

IWDC की पहली बैठक में नदी परिभ्रमण पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपये का की प्रतिबद्धता व्यक्त की

8 जनवरी 2024 को, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (**IWDC**) की पहली बैठक में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने भारत में नदी परिभ्रमण पर्यटन के विकास के लिए **45,000 करोड़ रुपये** के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- इस राशि में से 35,000 करोड़ रुपये परिभ्रमण जहाजों के लिए आवंटित किए गए हैं और 10,000 करोड़ रुपये 2047 (अमृत काल के अंत) तक परिभ्रमण अवसान बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अलग रखे गए हैं।
- केंद्रीय मंत्री ने बैठक के दौरान **'हरित नौका- अंतर्देशीय जहाजों के हरित संक्रमण के लिए दिशानिर्देश'** और **'नदी परिभ्रमण पर्यटन रोडमैप, 2047'** भी लॉन्च किया।

बैठक के बारे में:

i.बैठक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कोलकाता डॉक कॉम्प्लेक्स में जहाज MV गंगा क्वीन पर आयोजित की गई थी।

ii.बैठक का आयोजन MoPSW के तहत भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए नोडल एजेंसी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

i.नदी परिभ्रमण पर्यटन अंतर्देशीय जलमार्गों को भारत में आर्थिक वृद्धि और वाणिज्य में सहायता करने में सक्षम बनाएगा।

ii.बैठक का आयोजन MoPSW के तहत भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए नोडल एजेंसी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा किया गया था।

हरित नौका के बारे में:

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करके अंतर्देशीय जलमार्गों के सतत विकास में योगदान करना है। ये व्यापक पर्यावरणीय उद्देश्यों और सतत विकास लक्ष्यों के साथ हैं।

नदी परिभ्रमण पर्यटन रोडमैप, 2047:

i.नदी परिभ्रमण पर्यटन के लिए 8 परिचालन जलमार्गों से बढ़कर 26 अतिरिक्त जलमार्गों में क्षमता का विस्तार करना।

ii.रात्रि प्रवास वाले परिभ्रमण सर्किट की संख्या 17 से बढ़ाकर 80 करें।

iii.नदी परिभ्रमण अवसानों की संख्या 15 से बढ़ाकर 185 करके अंतर्देशीय जलमार्ग बुनियादी ढांचे को बढ़ाएं, जो 1233% की वृद्धि दर्शाता है।

iv.2047 तक रात्रि प्रवास के साथ परिभ्रमण पर्यटन यातायात को 5,000 से बढ़ाकर 1.20 लाख करना।

- जबकि राष्ट्रीय जलमार्गों पर रात्रि विश्राम के बिना स्थानीय परिभ्रमण पर्यटन यातायात को 2047 तक 2 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया जाएगा।

ध्यान देने योग्य

i.MoPSW प्रयासों का लक्ष्य अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) मोडल शेयर को 2% से बढ़ाकर 5% करना है, साथ ही 2047 तक कार्गो मात्रा को ~120 MTPA से 500 MTPA तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

ii.IWT इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, हाइड्रोजन और डेरिवेटिव जैसे पर्यावरण-अनुकूल प्रणोदन ईंधन को बढ़ावा देता है।

- प्रारंभ में, 8 इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज तैनात किए गए थे, जिन्हें रणनीतिक रूप से तीर्थ स्थलों पर तैनात किया गया था, जिनमें से दो राष्ट्रीय जलमार्ग -1 पर अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में और दो राष्ट्रीय जलमार्ग -2 पर गुवाहाटी में तैनात किए गए थे।

iii.मेरीटाइम अमृत काल विजन 2047 भारत की 7500 km लंबी तटरेखा का विकास करेगा और 46 चिन्हित पहलों के माध्यम से समावेशी वृद्धि और रोजगार के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग क्षमता का उपयोग करेगा।

- प्रमुख कदमों में बंदरगाह-आधारित समूह केंद्र स्थापित करना, उत्पादन/मांग केंद्रों के पास तटीय बर्थ और सड़क/रेल/IWT कनेक्टिविटी बढ़ाना शामिल है।

बातें प्रमुख लोग:

केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) श्रीपद नाइक और शांतनु ठाकुर, MoPSW मंत्री, राज्य सरकारों के साथ, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और अन्य प्रमुख हितधारक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हाल के संबंधित समाचार:

i.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 से 19 अक्टूबर, 2023 तक मुंबई के MMRDA ग्राउंड में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (GMIS) 2023 के तीसरे संस्करण का वस्तुतः उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान, प्रधान मंत्री ने 'अमृत काल विजन 2047-ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन मेरीटाइम ब्लू इकॉनमी' का अनावरण किया।

ii.DP वर्ल्ड, एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) ने 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के एक महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर किए और इसका उद्देश्य वाधवन बंदरगाह के विकास के लिए है, जो अरब तट के साथ मुंबई के उत्तर में स्थित एक बहुप्रतीक्षित परियोजना है।

बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बारे में:

केंद्रीय मंत्री - सर्बानंद सोनोवाल, (राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र - असम)

राज्य मंत्री (MoS) – श्रीपाद येसो नाइक; शांतनु ठाकुर

SUMMITS, EVENTS & CONFERENCE

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024: 26.33 लाख करोड़ रुपये के 41,299 MoU पर हस्ताक्षर

गुजरात सरकार ने 10 से 12 जनवरी, 2024 तक महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में 26.33 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (**VGGS**) 2024 के **10वें** संस्करण पर निवेश के इरादे पर 41,299 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- इस वर्ष के समिट का विषय 'गेटवे टू द फ्यूचर' है।
- समिट में 35 भागीदार देशों और 14 भागीदार संगठनों ने भाग लिया।
- समिट का उपयोग उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में भी किया जा रहा है।

आयोजन की मुख्य झलकियाँ

अधिकांश निवेश प्रस्ताव शहरी विकास, खनिज, रसायन, पेट्रोकेमिकल, पशुपालन और मछली पकड़ने, बिजली, तेल & र गैस, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और परिधान में हैं।

i.समिट में 140 से अधिक देशों के 61000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- समिट में तीन देशों के राष्ट्रपतियों- फ़िलिप न्यूसी (मोज़ाम्बिक), जोस रामोस-होर्टा (तिमोर-लेस्ते) और पेट्र पावेल (चेक गणस्टेट) ने भाग लिया।
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान VGGS 2024 के मुख्य अतिथि थे।

ii.प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए:

- PM ने 'द समिट ऑफ सक्सेस टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ फुल्लेस्ट पोटेंशियल ऑफ गुजरात' शीर्षक से एक ई-कॉफी टेबल बुक लॉन्च की।
- अमृत काल के पहले वाइब्रेंट गुजरात-2024 समिट के सम्मान में **20 रुपये** का स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया।
- वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के **20 वर्ष** सफलतापूर्वक पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट।
- इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा वाइब्रेंट गुजरात के दो दशक के असर पर प्रभाव अनुसंधान रिपोर्ट।

iii.VGGS में भाग लेने वाले उद्योग जगत के नेताओं ने गुजरात में 2.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का वादा किया है।

USISPF भागीदार संगठन के रूप में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल हुआ

2017 में गठित US-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम **(USISPF)** एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी और गैर-पक्षपातपूर्ण संगठन है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन, D.C. में है, इसके कार्यालय दोनों देशों (भारत और US) में हैं, यह व्यापार और सरकार के बीच की खाई को पाटता है और सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की साझेदारी को बढ़ावा देता है।

- यह सेल्सफोर्स, एबट, ब्लैकस्टोन, HSBC, UPS, माइक्रोन, सिस्को, SHRM और अन्य सहित 35 फॉर्च्यून अमेरिकी कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेगा।
- एमर्सन के अध्यक्ष और CEO लाल करसनभाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
- USISPF के अध्यक्ष & CEO डॉ. मुकेश अघी प्रतिनिधिमंडल का सह-नेतृत्व करेंगे।
- कंपनियां प्रमुख गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT) सिटी के आर्थिक परिदृश्य को आगे बढ़ाने के अवसरों की भी उत्सुकता से तलाश कर रही हैं।

प्रतिनिधिमंडल का ध्यान उच्च तकनीक विनिर्माण क्षेत्र में विशेष रूप से अर्धचालक और चिप निर्माण के साथ-साथ ऊर्जा संक्रमण, रसायन और औद्योगिक विनिर्माण, एयरोस्पेस और रक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की गति का लाभ उठाना है।

भारत, UAE ने गुजरात समिट में चार MoU पर हस्ताक्षर किए, UAE के DP वर्ल्ड ने गुजरात सरकार के साथ 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के MoU पर हस्ताक्षर किए

VGGS के मुख्य अतिथि, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने VGGS के मौके पर द्विपक्षीय बैठक की।

भारत और UAE के बीच इन क्षेत्रों में चार MoU पर हस्ताक्षर किए गए

- नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में निवेश सहयोग
- नवोन्मेषी स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाएँ
- खाद्य पार्क विकास
- और 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ नए पोर्टों, टर्मिनलों और आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए UAE के DP वर्ल्ड के साथ MoU।

टोरेंट पावर ने 47,350 करोड़ रुपये के निवेश के लिए गुजरात सरकार के साथ 4 MoU पर हस्ताक्षर किए

टोरेंट पावर ने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 47,350 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए गुजरात सरकार के साथ चार प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 MoU हैं

i.बनासकांठा, जामनगर, पाटन और सुरेंद्रनगर जिलों में 30650 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 3450 मेगावाट (MW) सोलर पावर प्रोजेक्ट और 1045 MW की हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स का विकास।

ii.4500 करोड़ रुपये की लागत से बनासकांठा जिले में 7000 MW की सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सोलर पार्क के बुनियादी ढांचे का विकास।

iii.7,200 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित निवेश के साथ बनासकांठा/दहेज में 100 KTPA की क्षमता वाली ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन सुविधा स्थापित करना।

iv.अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, दहेज SEZ और मंडल बेचराजी SIR (MBSIR) सिटी में टोरेंट पावर के डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश।

एरिशा ई-मोबिलिटी ने ग्रीन हाइड्रोजन और मेगा EV पार्क के लिए गुजरात सरकार के साथ 6,900 करोड़ रुपये का MoU पर हस्ताक्षर किया

MoU में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पार्क की स्थापना और पूरे गुजरात में 100 अत्याधुनिक EV चार्जिंग हब की तैनाती शामिल है।

- ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए एक इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए 5000 करोड़ रुपये का निवेश जिससे 4000 लोगों (प्रत्यक्ष+अप्रत्यक्ष) को रोजगार मिलेगा।
- 1500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 320 एकड़ में फैला अपनी तरह का पहला EV पार्क भी गुजरात में स्थापित किया जाएगा, जिससे 5000 लोगों को रोजगार (प्रत्यक्ष+अप्रत्यक्ष) मिलेगा।
- एरिशा E मोबिलिटी पूरे गुजरात में 100 अत्याधुनिक EV चार्जिंग हब स्थापित करेगी।

अन्य महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन

कंपनी	के साथ MoU	उद्देश्य	जगह	प्रस्तावित निवेश	अवधि

इन्फ़ीबीम एवेन्यूज़	गुजरात सरकार	भुगतान और प्लेटफार्मों के लिए एक आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) केंद्र स्थापित करना	GIFT सिटी	2,000 रुपये करोड़	2030 तक
इरोज इन्वेस्टमेंट्स	गुजरात सरकार	भारत का पहला AI पार्क विकसित करना, जिसे इमर्सो AI पार्क और एक AI विश्वविद्यालय कहा जाता है	GIFT सिटी	16000 करोड़ रुपये	2025 के मध्य तक
मारुति सुजुकी		दूसरा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना (प्रति वर्ष 10 लाख इकाइयों की स्थापित प्रोडक्शन क्षमता के साथ)	गुजरात	35000 करोड़ रुपये	2028-29 तक
IBM	CTE (तकनीकी शिक्षा आयुक्तालय) गुजरात	AI और साइबर सुरक्षा शिक्षा का विकास	गुजरात	–	–
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL)	गुजरात सरकार	10,000 MW की रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स का विकास	गुजरात	70000 करोड़ रुपये	
IPL बायोलॉजिकल	गुजरात सरकार	क्षेत्र में अत्याधुनिक जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैव कवकनाशी और सूक्ष्मजीव विकास प्रवर्तक सुविधा स्थापित करना	गुजरात	400 करोड़ रुपये	2030 तक
DCM श्रीराम	गुजरात सरकार	रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्माण के लिए	भरूच	12,000 करोड़ रुपये	2028 तक
दक्षिण कोरियाई सिमटेक	गुजरात सरकार	सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए एक इकाई स्थापित करने के लिए	सनद	1250 करोड़	

NHPC	गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GPCL)	750 MW कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में निवेश करना	छोटा उदयपुर, गुजरात	4000 करोड़ रुपये	
शंघाई का NDB (न्यू डेवलपमेंट बैंक)	गुजरात सरकार	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु लगभग 1200 km सड़क निर्माण हेतु ऋण समझौता निर्धारित		500 मिलियन अमेरिकी डॉलर	
इंस्टाशील्ड संकेत	गुजरात सरकार	नागरिकों को कोरोना वायरस परिवार के विभिन्न प्रकारों सहित मौजूदा और बढ़ते वायरस से बचाने के लिए 'रिवॉल्यूशनाइज़िंग वायरस डिसरप्शन' नामक प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए।		45 करोड़ रुपये	
NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GSPC) और गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड (GPPL)	GPPL द्वारा प्रदान की गई भूमि पर निर्यात और घरेलू बाजार के लिए ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन सहित एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित करना और गुजरात में अपतटीय पवन फार्मों की खोज, विकास और संचालन के लिए NGEL द्वारा एक लंगर पोर्ट के रूप में पिपावाव पोर्ट के विकास का पता लगाना।			

वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट के बारे में

i.वाइब्रेंट गुजरात, जिसे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट भी कहा जाता है, एक द्विवार्षिक निवेशकों का ग्लोबल व्यापार कार्यक्रम है जो गुजरात स्टेट में आयोजित किया जाता है।

ii.VGGS 2003 में भारत के माननीय PM (गुजरात के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री) श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ।

गुजरात के बारे में

मुख्यमंत्री - भूपेन्द्रभाई पटेल

राज्यपाल– आचार्य देवव्रत

राजधानी – गांधीनगर

दावोस 2024: स्विट्जरलैंड के दावोस में WEF की 54वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की 54वीं वार्षिक बैठक, जिसे "दावोस शिखर सम्मेलन 2024" के रूप में भी जाना जाता है, 15 से 19 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के स्विस अल्पाइन स्कूल, दावोस में आयोजित की गई थी।
2024 शिखर सम्मेलन का विषय **"रीबिल्डिंग ट्रस्ट"** है।

WEF 2024:

i.इस कार्यक्रम में 60 राष्ट्राध्यक्षों और सरकारी अधिकारियों सहित 2800 से अधिक नेताओं ने भाग लिया।
ii.बैठक ने पारदर्शिता, निरंतरता और जवाबदेही सहित विश्वास को बढ़ाने वाले बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मंच की पेशकश की।
iii.5 दिनों की अवधि में कुल 21 सत्र आयोजित किए गए।
नोट: WEF शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर दावोस में आयोजित किया जाता है।

मुख्य फोकस क्षेत्र:

i.बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सुरक्षा और सहयोग हासिल करना
ii.नए युग के लिए विकास और नौकरियाँ पैदा करना
iii.आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में
iv.जलवायु प्रकृति और ऊर्जा के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति:

प्रमुख लोगों:

i.बैठक के प्रतिभागियों में प्रमुख राजनीतिक नेताओं में चीन के प्रधान मंत्री (PM) ली क्वांग; इमैनुएल मैक्रॉन, फ्रांस के राष्ट्रपति; वलोडिमिर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति; यूरोपीय संघ (EU) आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन; संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली शामिल हैं।
ii.एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव (SG); अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा; विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा; और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के महानिदेशक (DG) नगोजी ओकोन्जो-इवेला ने भी बैठक में भाग लिया।

भारत से प्रतिनिधि:

i.WEF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्रियों: स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री; हरदीप सिंह पुरी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) और अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और राजेश कुमार (RK) सिंह, सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य & उद्योग मंत्रालय (MoCI) ने किया।

भारत ने एक लचीली ग्लोबल अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत एक लचीली ग्लोबल अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है और स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) में निवेश के लिए पसंदीदा स्थान है।

i.भारत चार अलग-अलग स्थानों: इंडिया एंगेजमेंट सेंटर, एक्सपीरियंस इंडिया सेंटर, इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर और वी लीड लाउंज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है।
ii.भारत निवेश केंद्र गवर्नमेंट-टू-बिज़नेस (**G2B**) और बिज़नेस-टू-बिज़नेस (**B2B**) नेटवर्किंग, गोलमेज सम्मेलनों और सत्रों की मेजबानी के केंद्र के रूप में काम करेगा।

भारत ने "ग्लोबल गुड अलायन्स फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी" लॉन्च किया

WEF 2024 के दौरान, भारत ने WEF के साथ साझेदारी में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण और निवेश को एक साथ लाने के लिए **"ग्लोबल गुड अलायन्स फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी"** लॉन्च किया।

प्रमुख लोग: इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी और WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब ने भाग लिया।

प्रमुख बिंदु:

i.गठबंधन का विचार G20 (ग्रुप ऑफ 20) नेताओं की घोषणा में संकल्पित किया गया था और प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित महिला सशक्तिकरण के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

ii.गठबंधन को भारतीय उद्योग परिसंघ **(CII) के महिला नेतृत्व केंद्र** द्वारा रखा और समन्वित किया जाएगा और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित किया जाएगा।

iii.WEF "नेटवर्क पार्टनर" होगा और इन्वेस्ट इंडिया गठबंधन का "संस्थागत भागीदार" होगा।

iv.एलायंस को मास्टरकार्ड, उबर, टाटा, TVS, गोदरेज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, IMD लॉज़ेन जैसे कई उद्योग जगत के नेताओं और उद्योग के 10000 से अधिक भागीदारों द्वारा भी समर्थन दिया जाएगा।

v.एंगेजमेंट ग्रुप की गतिविधियां और G20 फ्रेमवर्क, बिजनेस20, वूमेन20 और G20 EMPOWER के तहत पहल से गठबंधन को बड़े ग्लोबल समुदाय के लाभ के लिए G20 नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने WEF दावोस में B20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की

WEF 2024 के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने **बिजनेस 20 (B20) ग्लोबल इंस्टीट्यूट** की स्थापना की घोषणा की। यह 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की प्रतिबद्धता के प्रयासों के अनुरूप है।

इस अवधारणा की कल्पना दिल्ली में आयोजित बिजनेस 20 (B20) शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान की गई थी।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य ग्लोबल मूल्य श्रृंखलाओं (GVC) को मजबूत करना, सामाजिक लाभ के लिए डिजिटल नवाचार और AI का उपयोग करना, ईएसजी सिद्धांतों को बढ़ावा देना और स्थिरता और ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करना है।

- **RAISE**- रेस्पोंसिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्वीटेबल बिजनेसेज़। यह पहल ग्लोबल साउथ की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को संबोधित करने के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

रोग X: WEF 2024 में अज्ञात स्वास्थ्य खतरे का खुलासा:

WEF 2024 में **'प्रीपेरिंग फॉर डिजीज X'** शीर्षक पर चर्चा के दौरान, स्वास्थ्य उद्योग के नेताओं ने एक काल्पनिक "डिजीज X" के प्रकोप के लिए पूर्व नियोजन के महत्व पर चर्चा की।

- डिजीज X एक रहस्यमय डिजीज है क्योंकि डिजीज का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। इसे COVID-19 के समान एक गंभीर सूक्ष्मजीवी खतरा माना जाता है।
- WHO ने 2017 में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम **(SARS)** और इबोला वायरस के साथ डिजीज X को रोगजनकों की प्राथमिकता सूची में जोड़ा।

भारत ट्रस्ट में ग्लोबल लीडर्स के रूप में उभरा: एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024

WEF 2024 से पहले जारी **"एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024"** के अनुसार, व्यवसायों और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) में विश्वास के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर है।

- **समग्र** सूचकांक (NGO, व्यवसाय, सरकार और मीडिया में औसत % विश्वास) पर, भारत 2024 में दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। यूनाइटेड किंगडम (UK) ने दक्षिण कोरिया को सबसे कम भरोसेमंद देश के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया।
- **2023** में, सर्वेक्षण की समग्र रैंकिंग में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया था।

नोट: एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 सर्वेक्षण का 24वां वार्षिक संस्करण है जिसमें 28 देशों के 32000 से अधिक उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है।

मुख्य निष्कर्ष:

i.सऊदी अरब ने सरकार में विश्वास के लिए पहला स्थान हासिल किया और चीन ने मीडिया में विश्वास के लिए पहला स्थान हासिल किया।

- मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत को चौथा और सरकार को पांचवां स्थान मिला।

ii.नियोक्ता श्रेणी में दिखाए गए विश्वास की शर्तों में इंडोनेशिया शीर्ष पर है जबकि भारत ने इस श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है।

iii.सर्वेक्षण से पता चला कि 17 देशों की सरकार पर भरोसा नहीं किया गया जिसमें: **USA, जर्मनी और ब्रिटेन** शामिल हैं।

iv.सर्वेक्षण के अनुसार, मीडिया ग्लोबली पर सबसे कम भरोसेमंद संस्थान रहा। 15 देशों में इसकी विश्वसनीयता सबसे कम है, जिनमें: **USA, जापान और ब्रिटेन** शामिल हैं।

ध्यान देने योग्य बातें:

i.रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में विश्वास का स्तर अधिक है।

ii.USA में, 67% (लगभग 2/3 उत्तरदाताओं) का मानना है कि विज्ञान का अत्यधिक राजनीतिकरण किया गया था।

iii.चीन में, 75% उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार और संगठन धन के माध्यम से विज्ञान पर प्रभाव डालते हैं।

iv.63% उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्लोबल लीडर्स झूठी जानकारी के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हैं।

v.इनफार्मेशन वॉर का डर 2023 की तुलना में 6 अंक बढ़ गया। यह आंकड़ा 61% है।

फिनटेक उद्योग में रेसिलिएंट ग्रोथ: WEF रिपोर्ट

"टुवर्ड्स रेसिलिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ" शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि फिनटेक कंपनियां विशेष रूप से अपने मुख्यालय के क्षेत्र में सीमाओं के पार परिचालन का विस्तार कर रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक संपन्न क्लस्टर या फिनटेक मुख्यालय की मेजबानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिचालन देशों में से एक है।

रिपोर्ट के बारे में:

i.यह रिपोर्ट WEF द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जज बिजनेस स्कूल में **कैम्ब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस (CCAF)** के साथ साझेदारी में तैयार की गई थी।

ii.रिपोर्ट में 5 खुदरा उद्योग क्षेत्रों और 6 क्षेत्रों: एशिया-प्रशांत, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, US और कनाडा, और उप-सहारा अफ्रीका में 200 से अधिक फिनटेक कंपनियों को शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

i.अध्ययन के अनुसार, फिनटेक के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग देशों में यूएसए, UK, सिंगापुर, मैक्सिको और भारत शामिल हैं।

ii.ग्लोबली पर, उद्योग क्षेत्रों और क्षेत्रों में औसत ग्राहक वृद्धि दर 50% से ऊपर है।

iii.उपभोक्ता वृद्धि फिनटेक क्षेत्र में वृद्धि का मुख्य कारक बनकर उभरी। लगभग 63% फिनटेक कंपनियां अपने नियामक माहौल को लेकर आशावादी हैं।

iv.रिपोर्ट में फिनटेक उद्योग के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों को रेखांकित किया गया है: व्यापक आर्थिक माहौल और फिनटेक फंडिंग में कमी। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024:

WEF द्वारा जारी "ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024" शीर्षक वाली रिपोर्ट में 3 प्रमुख जलवायु जोखिमों: चरम मौसम की घटनाएं, पृथ्वी प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन पर प्रकाश डाला गया है, शीर्ष ग्लोबल चुनौतियों के रूप में जिन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
यह वार्षिक रिपोर्ट WEF द्वारा आयोजित ग्लोबल रिस्क धारणा सर्वेक्षण पर आधारित है जिसमें शिक्षा, व्यवसाय और सरकार के 1500 विशेषज्ञ शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

i.कुल मिलाकर रिपोर्ट में 2024 के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण है।
ii.गलत सूचना और दुष्प्रचार से समाज में अविश्वास बढ़ेगा और यह अगले 2 वर्षों में विशेष रूप से भारत के लिए सबसे बड़ा ग्लोबल रिस्क है।

- **AI** से उत्पन्न गलत सूचना गलत सूचना फैलाने के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति होगी और इसमें देशों में चुनावों का ध्रुवीकरण करने की क्षमता है।

iii.रिपोर्ट के अनुसार, 63% उत्तरदाताओं का मानना है कि पर्यावरण जोखिम लंबी अवधि के लिए सबसे बड़ा जोखिम था।
iv.गलत सूचना और जलवायु परिवर्तन के अलावा, आर्थिक अस्थिरता और मुद्रास्फीति ग्लोबल रिस्क पैदा करती है। आर्थिक अनिश्चितता के लिए मुख्य योगदानकर्ता जीवन यापन की लागत में वृद्धि और AI होगा।

सिफ़ारिशें:

i.स्थानीयकृत निवेश इन ग्लोबल रिस्क के प्रभाव को विनियमित करने में मदद करेगा।
ii.यह अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर देता है लेकिन व्यक्तिगत प्रयासों से अधिक सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

CII इंडिया बिजनेस हब दावोस में लॉन्च किया गया

i.CII के अध्यक्ष दिनेश और CII के DG चरणजीत बनर्जी ने स्विट्जरलैंड के दावोस में **"CII इंडिया बिजनेस हब"** लॉन्च किया। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए मंच के रूप में कार्य करेगा। यह हब CII के **"क्रेडिबल इंडिया"** विषय वाले अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारत की हालिया उपलब्धियों को उजागर करेगा जैसे: प्रक्रियाओं का सरलीकरण, पुराने कानूनों को हटाना, बुनियादी ढांचे का विकास और बहुत कुछ।

महाराष्ट्र सरकार ने WEF 2024 में ~3 लाख करोड़ रुपये के MoU पर हस्ताक्षर किए

महाराष्ट्र ने स्विट्जरलैंड के दावोस में WEF 2024 में 3,53,675 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
ये MoU महाराष्ट्र में 2 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करेंगे।

प्रमुख बिंदु:

i.WEF 2024 के पहले दिन के दौरान, 6 उद्योगों के साथ 1,02,000 करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 26000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
ii.WEF 2024 के दूसरे दिन, 8 उद्योगों के साथ 2,08,850 करोड़ रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें 1.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है।
iii.WEF 2024 के तीसरे दिन, 6 उद्योगों के साथ 42,825 करोड़ रुपये के MoU पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 13000 नौकरियां पैदा करने की क्षमता है।

नोट:

i.बर्कशायर हैथवे और ग्रीनको एनर्जी परियोजनाओं जैसे ग्लोबल दिग्गजों के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
ii.ये MoU ग्लोबल निवेशकों के लिए भारत के स्थिर और भरोसेमंद प्रवेश द्वार के रूप में राज्य की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगे।

iii.शिखर सम्मेलन के दौरान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (CM) एकनाथ शिंदे ने श्नाइडर इलेक्ट्रिक और लुईस ड्रेफस जैसे व्यापारिक दिग्गजों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।

अदानी ग्रुप & महाराष्ट्र ने डेटा सेंटरों में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

अदानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने हाइपरस्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की **1GW (गीगावाट)** क्षमता स्थापित करने के लिए 10 वर्षों में **50,000 करोड़ रुपये** का निवेश करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

- दावोस में WEF 2024 में महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और अदानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अदानी की उपस्थिति में MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

i.डेटा केंद्र पुणे और नवी मुंबई में स्थापित किए जाएंगे और नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होंगे।
ii.यह 20000 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा।

हुंडई इंडिया ने जनरल मोटर के तालेगांव प्लांट का अधिग्रहण किया

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने घोषणा की कि उसने महाराष्ट्र में जनरल मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (GMI) के तालेगांव प्लांट का अधिग्रहण कर लिया है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र में 6000 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

- दावोस (स्विट्जरलैंड) में WEF 2024 के दौरान हुंडई इंडिया के CEO अन सू किम और महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत के बीच MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रमुख बिंदु:
i.हुंडई की उत्पादन क्षमता **8 लाख से अधिक से बढ़कर 1 मिलियन** होने की उम्मीद है।
ii.1.3 लाख इकाइयों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र में 2025 में विनिर्माण फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि:
GMI और HMIL ने मार्च 2023 में संयंत्र के अधिग्रहण के लिए टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए और HMIL ने अगस्त 2023 में GMI के साथ खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए।

आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र का पहला हरित अमोनिया संयंत्र स्थापित करेगा

INOX एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने महाराष्ट्र का पहला ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

- यह संयंत्र 3 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश से विकसित किया जाएगा और इसकी उत्पादन क्षमता 5 लाख MTPA(मीट्रिक टन प्रति वर्ष) होगी।

नोट: INOX एयर प्रोडक्ट्स INOX ग्रुप और USA स्थित एयर प्रोडक्ट्स & केमिकल्स इंक का एक संयुक्त उद्यम है।

प्रमुख बिंदु:
i.परियोजना को 3 से 5 वर्षों में चालू करने का लक्ष्य है।
ii.यह तरल अमोनिया का उत्पादन करेगा जो जलवायु-तटस्थ हाइड्रोजन वाहक हो सकता है।
प्रमुख लोग: महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे, सिद्धार्थ जैन (प्रमोटर और निदेशक, आईनॉक्स ग्रुप) और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

तेलंगाना & WEF ने हैदराबाद में WEF C4IR स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

WEF 2024 शिखर सम्मेलन के मौके पर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद, तेलंगाना में WEF के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र **(C4IR)** की स्थापना के लिए WEF अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह भारत का पहला विषयगत केंद्र होगा।

i.C4IR को फरवरी, 2025 में हैदराबाद में होने वाले बायो एशिया (2025) में लॉन्च किया जाएगा।

ii.महत्व: यह जीनोमिक्स और स्वास्थ्य सेवा विनिर्माण जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देगा।

तेलंगाना & अदानी ग्रुप ने 12400 करोड़ रुपये के 4 MoU पर हस्ताक्षर किए

तेलंगाना सरकार ने स्विट्जरलैंड के दावोस में WEF 2024 वार्षिक शिखर सम्मेलन में 12400 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए अदानी ग्रुप के तहत कंपनियों के साथ 4 MoU पर हस्ताक्षर किए। MoU का उद्देश्य तेलंगाना के आर्थिक विकास के लिए ऐसी नींव तैयार करना है जो हरित, टिकाऊ, समावेशी और परिवर्तनकारी हो।

हस्ताक्षरकर्ता: समझौते पर तेलंगाना के CM A रेवंत रेड्डी और अदानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अदानी के बीच हस्ताक्षर किए गए।

अदानी ग्रुप & तेलंगाना के बीच MoU का विवरण

i.अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) तेलंगाना में 100 MW (मेगावाट) डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 5000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। यह अगले 5-7 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा और 600 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा।

ii.अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) कोयाबेस्टगुडेम में 850 MW और नाचराम में 500 MW की दो पप स्टोरेज परियोजना स्थापित करने के लिए 5000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी।

iii.अंबुजा सीमेंट्स 6 MTPA सीमेंट प्लांट स्थापित करेगी जो 1400 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। इससे 4000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसे अगले 5 वर्षों में चालू कर दिया जाएगा।

iv.अदानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अगले 10 वर्षों में अदानी एयरोस्पेस पार्क में अनुसंधान विकास, डिजाइन निर्माण और काउंटर-ड्रोन और मिसाइल सिस्टम के एकीकरण में 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगा। इससे 1000 से अधिक नौकरियाँ पैदा होने का अनुमान है

WEF बैठक में कर्नाटक ने 23000 करोड़ रुपये के MoU पर हस्ताक्षर किए

कर्नाटक सरकार ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित WEF 2024 में ग्लोबल कंपनियों के साथ 23,000 करोड़ रुपये के 8 MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

राज्य प्रतिनिधिमंडल ने ग्लोबल उद्योग जगत के नेताओं: नेस्ले, HP, HC, वोल्वो ग्रुप, IKEA, सोनी माइक्रोसॉफ्ट, हिताची के साथ 50 से अधिक रणनीतिक बैठकें कीं।

मुख्य विचार:

i.वेब वर्क्स ने बेंगलुरु में 100 MW डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 20000 करोड़ रुपये का निवेश करने का फैसला किया है। इससे 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

ii.हिताची ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

iii.लुलु ग्रुप ने विजयपुर में 300 करोड़ रुपये की एक नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने और अपनी मौजूदा इकाई कलबुर्गी के विस्तार में और निवेश करने की योजना बनाई है। BL आर्गो की विजयपुर में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की भी योजना है।

iv.AB InBev इंडिया कर्नाटक में अपनी शराब इकाई की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए 400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

v.स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा समाधान और डेटा केंद्रों की दिशा में विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

WEF ने फ़्लूइड एनालिटिक्स को शीर्ष प्रर्वतक का नाम दिया

कैलिफोर्निया (USA) स्थित वेस्टवाटर एनालिटिक्स कंपनी, **फ्लुइड एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड** को स्विट्जरलैंड में WEF 2024 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में ग्लोबल फ्रेशवाटर कन्सेर्वटिव की दिशा में उनके काम के लिए **शीर्ष प्रर्वतक** नामित किया गया था।

पुरस्कार के बारे में:

i.यह पुरस्कार अप लिंक द्वारा दिया जाता है जो WEF का खुला नवाचार मंच है। अप लिंक के साथ साझेदारी में HCL टेक का लक्ष्य अपनी तरह का पहला इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है जो जल केंद्रित उद्यमियों का समर्थन करेगा।

ii.विजेताओं का चयन जल केंद्रित शून्य जल अपशिष्ट चुनौती के माध्यम से किया गया, जिसके लिए इस वर्ष 192 ग्लोबल कंपनियों से आवेदन प्राप्त हुए।

फ्लुइड एनालिटिक्स के बारे में:

i.फ्लूइड एनालिटिक्स, जिसे पहले फ्लूइड रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, की स्थापना असीम R भालेराव और एक्यूमेन फेलो, निधि जैन ने की थी।

ii.यह पानी और अपशिष्ट जल के बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए AI तकनीक का उपयोग करता है।

नोट: फ़्लूइड एनालिटिक्स की कनाडा (टोरंटो) और भारत (पुणे, महाराष्ट्र) में भी उपस्थिति है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के बारे में:

संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष– प्रोफेसर क्लाउस श्वाब

प्रबंध निदेशक (MD)– सादिया जाहिदी

मुख्यालय– कोलोनी, जिनेवा कैंटन, स्विट्जरलैंड

स्थापित– 1971

युगांडा ने G77+चीन तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन की मेजबानी की: भारत ने भविष्य के विकास इंजन के रूप में वैश्विक दक्षिण की भूमिका का चैंपियन बनाया

21-23 जनवरी 2024 को **युगांडा** के कंपाला में आयोजित 77+चीन समूह (**G-77+चीन) तीसरे दक्षिण शिखर** सम्मेलन मे विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री V.मुरलीधरन ने भारत का प्रतिनिधित्व और के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने दुनिया के "भविष्य के विकास इंजन" के रूप में वैश्विक दक्षिण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

- (G-77+चीन) तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का **विषय "लीविंग नो वन बिहाइंड."** था।
- तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन की मेजबानी H.E. राष्ट्रपति **योवेरी कगुटा मुसेवेनी** की अध्यक्षता में युगांडा गणराज्य द्वारा की गई थी।

ध्यान देने योग्य बातें:

i.भारत अपने विकास के अनुभव को भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के साथ साझा करता है, जो अब 160 भागीदार देशों तक फैला हुआ है।

ii.भारत LDC वस्तुओं को बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए सबसे कम विकसित देशों (LDC) के लिए 2008 में शुल्क मुक्त व्यापार वरीयता योजना की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया।

मुख्य विशेषताएं:

MoS ने निम्नलिखित की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया:

- वैश्विक दक्षिण प्रतिबद्धताओं की पुनः पुष्टि;
- नवीन विकास समाधानों की खोज करना;
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला में सुधार; और
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना।

उद्देश्य:

i.(G-77) तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन विकासशील देशों का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र (UN) अंतरसरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, गरीबी आदि क्षेत्रों सहित दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना है।

ii.शिखर सम्मेलन के दौरान, **135** सदस्य देशों (**चीन** सहित) ने एकजुटता, एकता और पूरकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

- इसका उद्देश्य सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की दिशा में काम करते हुए एक सामूहिक और एकीकृत आवाज सुनिश्चित करना है।

नोट: दक्षिण शिखर सम्मेलन G-77 का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।

अध्यक्षता:

i.यह G-77 के संगठनात्मक ढांचे के भीतर सर्वोच्च राजनीतिक निकाय है।

ii.यह क्षेत्रीय आधार पर (अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के बीच) घूमता है और सभी अध्यायों में 1 वर्ष के लिए आयोजित किया जाता है।

iii.वर्ष 2024 के लिए, युगांडा गणराज्य के पास न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में G-77 की अध्यक्षता है।

iv.क्यूबा ने **2023** में G-77 की अध्यक्षता संभाली।

परियोजनाओं के लिए स्रोत:

77 प्रायोजकों का समूह दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए पेरेज़-ग्युरेरो ट्रस्ट फंड **(PGTF)** से वित्त पोषण के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर परियोजनाएं चलाता है।

G77 की स्थापना:

i.G-77 की स्थापना जून 1964 में 77 विकासशील देशों द्वारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में व्यापार और विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) सत्र में "सत्तर-सात विकासशील देशों की संयुक्त घोषणा" के बाद की गई थी।

- पहला और दूसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन क्रमशः 2000 में हवाना, क्यूबा में और 2005 में दोहा, कतर में आयोजित किया गया था।

ii.2024 में G77 की **60वीं** वर्षगांठ है, भारत ने 1970-71 में समूह की पहली अध्यक्षता संभाली थी।

हाल के संबंधित समाचार:

NASSCOM- डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI) एनुअल इनफार्मेशन सिक्योरिटी समिट (AISS) का 18वां संस्करण, 3 दिवसीय कार्यक्रम 19 से 21 दिसंबर 2023 तक लीला एंबियंस होटल, गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित किया गया था।

<u>युगांडा के बारे में:</u>

राजधानी– कंपाला

प्रधान मंत्री– रोबिनाह नब्बनजा

मुद्रा– युगांडा शिलिंग

19वां NAM शिखर सम्मेलन कंपाला, युगांडा में आयोजित हुआ; EAM S जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया

केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर, विदेश मंत्रालय (MEA) ने 19-20 जनवरी **2024** को **युगांडा के कंपाला** में स्पेक रिज़ॉर्ट कन्वेंशन सेंटर, मुन्योन्यो में आयोजित **19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) राष्ट्राध्यक्षों और सरकारी शिखर सम्मेलन** में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

- शिखर सम्मेलन के दौरान, **युगांडा** ने 2024-2027 के लिए **NAM की अध्यक्षता** ग्रहण की। युगांडा ने **अज़रबैजान**(2019-2023) से नेतृत्व संभाला।
- युगांडा के राष्ट्रपति **योवेरी कागुटा मुसेवेनी** को **19वें NAM शिखर सम्मेलन** के **अध्यक्ष** के रूप में चुना गया और उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति H.E. इल्हाम अलीयेव से पदभार ग्रहण किया।

19वें NAM शिखर सम्मेलन का विषय: 'डीपेनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएन्स'

भागीदारी: शिखर सम्मेलन में भारत, नेपाल, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम और ईरान जैसे **120** से अधिक विकासशील देशों की भागीदारी देखी गई।

नोट: NAM शिखर सम्मेलन आमतौर पर हर तीन साल में एक बार होता है। 18वां NAM शिखर सम्मेलन 25-26 अक्टूबर, 2019 को बाकू, अज़रबैजान में आयोजित हुआ था।

प्रमुख बिंदु:

i.शिखर सम्मेलन से पहले मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर विचार-विमर्श हुआ। डॉ. राजकुमार रंजन सिंह, राज्य मंत्री (MoS), MEA ने NAM विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

ii.शिखर सम्मेलन के मौके पर, विदेश मंत्री (EAM) डॉ. जयशंकर ने युगांडा नेतृत्व और NAM सदस्य देशों के समकक्षों के साथ बैठक की।

iii.उन्होंने मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी के संबंध में चल रही उच्च स्तरीय वार्ता पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर से मुलाकात की।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के बारे में:

i.गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का विचार इंडोनेशिया के बांडुंग में 18-24 अप्रैल 1955 को आयोजित प्रथम बड़े पैमाने के एशियाई-अफ्रीकी या अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन (जिसे बांडुंग सम्मेलन के रूप में जाना जाता है) के दौरान उत्पन्न हुआ था।

ii.NAM की औपचारिक स्थापना 1-6 सितंबर 1961 को बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में आयोजित प्रथम (I) शिखर सम्मेलन में की गई थी।

iii.संयुक्त राष्ट्र (UN) के बाद NAM दुनिया भर में राज्यों का सबसे बड़ा समूह है।

सदस्य: 120 सदस्य देश (अफ्रीका (53); अमेरिका और कैरेबियाई (26); एशिया और प्रशांत (39); और यूरोप (2); **18 पर्यवेक्षक देश**; और **10 पर्यवेक्षक संगठन**।

अतिरिक्त जानकारी: V. मुरलीधरन, MoS,MEA ने 21-22 जनवरी को कंपाला, युगांडा में आयोजित G-77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

9वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित हुआ

इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल **(IISF 2023)** का **9वां संस्करण** 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित किया गया था। इस फेस्टिवल का उद्देश्य साइंस और टेक्नोलॉजी के अग्रणी क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाना है।

- IISF 2023 **केंद्रीय विषय - 'साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल'** के तहत आयोजित किया जाता है।

उद्देश्य: साइंस के प्रति उत्साही लोगों को पहचानना, छात्रों में साइंटिफिक क्यूरोसिटी को बढ़ावा देना और भारतीय नागरिकों के बीच साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स (STEM) को बढ़ावा देना।

IISF 2023 के बारे में:

i.स्थान: फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस & टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (THSTI) का परिसर और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस & टेक्नोलॉजी (RCB) के रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी (RCB)।

ii.आयोजक: डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (DST), MoST।

iii.समन्वय और कार्यान्वयन निकाय: नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन - भारत, DST का स्वायत्त निकाय।

iv.प्रतिभागी: IISF 2023 में लगभग 22 देशों ने भाग लिया। इनमें अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, केन्या, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, नामीबिया, फिलीपींस,

रवांडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम (UK), संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), वियतनाम और जिम्बाब्वे शामिल हैं।

v.साइंटिफिक & इंडस्ट्रियल रिसर्च (**CSIR**)-नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन & पॉलिसी रिसर्च (**NIScPR**) में साइंस मीडिया कम्युनिकेशन सेल (**SMCC**) ने IISF 2023 के मीडिया कवरेज का समन्वय और सुविधा प्रदान की।

उद्घाटन & समापन समारोह:

i.केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) (स्वतंत्र प्रभार) **डॉ. जितेंद्र सिंह**, MoST ने 17 जनवरी 2024 को IISF 2023 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

ii.हरियाणा के मुख्यमंत्री (CM) **मनोहर लाल खट्टर** ने मुख्य अतिथि के रूप में IISF 2023 के समापन समारोह में भाग लिया।

- उन्होंने यह भी घोषणा की कि हरियाणा सरकार की फरीदाबाद (हरियाणा) में 50 एकड़ में फैली एक अत्याधुनिक साइंस सिटी विकसित करने की योजना है।

प्रमुख लोग:

प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय सूद; सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभय करंदीकर; सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राजेश गोखले; सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, M रविचंद्रन; दूसरों के बीच में भाग लिया।

मुख्य विशेषताएं:

i.IISF 2023 में 17 कार्यक्रम शामिल थे जिनमें स्टूडेंट साइंस विलेज, फेस टू फेस ऑफ न्यू फ्रंटियर्स ऑफ साइंस & टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल - स्पेस हैकथॉन, यंग साइंटिस्ट्स कांफ्रेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एक्सहिबिशन आदि शामिल हैं।

ii.IISF ने समाज में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए लगभग एक महीने तक R&D इंस्टीट्यूट, लैब्स और स्कूलों में आउटरीच कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी आयोजित की।

iii.IISF 2023 में कई समझौता ज्ञापनों (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए।

साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक्सहिबिशन:

i.मेगा साइंस एक्सपो में 100 से अधिक स्टॉल प्रदर्शित किए गए। 20 स्टॉल निजी संगठनों के थे और 80 से अधिक स्टॉल सरकारी संस्थाओं के थे। प्रदर्शनी ने लगभग 1 लाख आगंतुकों को आकर्षित किया।

ii.प्रमुख संगठन, जैसे कि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गेनाईजेशन (DRDO), इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन (ISRO), मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस (MoES), और DST और इसके स्वायत्त निकाय एक्सपो में अपने इन्वेंशंस और इनोवेशंस का प्रदर्शन करते हैं।

अवार्ड:

मेगा साइंस एक्सपो में प्रतिभागियों को विभिन्न श्रेणियों के तहत कई अवार्ड दिए गए।

पद	विजेता
बेस्ट कॉन्सेप्टुअल पवेलियन	
1	रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI), बेंगलुरु, कर्नाटक
2	DST, गुजरात सरकार

3	टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (TDB), DST
बेस्ट टेक्नोलॉजी पवेलियन	
1	डिफेन्स रिसर्च & डेवलपमेंट आर्गेनाईजेशन (DRDO), मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स
2	BrahMos एयरोस्पेस
बेस्ट इंटरैक्टिव पवेलियन	
1	नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओसियन रिसर्च (NCPOR), मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज (MoES)
2	इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन (ISRO), डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस (DoS)
जूरी स्पेशल मेंशंड अवार्ड	
1	इंडियन कॉउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR)
2	एमिटी यूनिवर्सिटी
बेस्ट पवेलियन इन द एक्सपो	
1	CSIR
2	डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
3	DST, MoST

NFSU का 5वां इंटरनेशनल और 44वां ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कांफ्रेंस गांधीनगर, गुजरात में आयोजित हुआ

23 जनवरी 2024 को, गृह मंत्रालय (MHA) के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर, गुजरात में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (**NFSU**) **में 5वें इंटरनेशनल और 44वें ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कांफ्रेंस** का उद्घाटन और संबोधित किया।

- NFSU और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी (ISC) द्वारा **"बिहेवियरल फोरेंसिक : रीइंटेग्रेटिंग एक्सपैंडिंग कॉन्टूर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनोलिस्टिक्स"** विषय पर कांफ्रेंस आयोजित किया गया था।
- केंद्रीय मंत्री ने क्षमता निर्माण और जांच का समर्थन करने के लिए NFSU में **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल फोरेंसिक** का भी उद्घाटन किया।

प्रमुख लोग: इस कार्यक्रम में भारत भर से न्यायाधीशों, कानूनी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, क्रिमिनोलॉजिस्ट्स, विद्वानों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

कांफ्रेंस के बारे में:

कांफ्रेंस का आयोजन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC), नेशनल कमीशन फॉर वीमेन (NCW), नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) और गुजरात स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सहयोग से किया गया था।

कांफ्रेंस के विषय:

i.क्रिमिनोलॉजी एंड बिहेवियरल फोरेंसिक: ट्रांसडीसकीप्लीनरी फॉउंडेशन्स
ii.कॉन्टूर्स ऑफ विक्टिम सपोर्ट, जस्टिस एंड चैलेंजेज
iii.कंटेम्पररी इश्यूज इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
iv.फोरेंसिक अल्गोरिथ्म्स इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) के बारे में:

NFSU नेशनल महत्व का एक संस्थान है और यह दुनिया का पहला और एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो फोरेंसिक, बिहेवियरल, साइबरसिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक और अलाइड साइंस के लिए समर्पित है।
इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा NFSU अधिनियम 2020 के माध्यम से की गई थी।
स्थान- गांधीनगर, गुजरात।

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भोपाल में दूसरे राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया

केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 23 जनवरी 2024 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित दूसरे राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु:

i.मध्य प्रदेश ने प्रथम रैंक हासिल की और वर्ष 2022-23 के लिए खनन नीलामी में अपने प्रयासों को मान्यता देने के लिए केंद्रीय मंत्री से पुरस्कार प्राप्त किया।

- इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश & कर्नाटक को भी सराहना का पुरस्कार मिला।

ii.सम्मेलन के दौरान मंत्री द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन (**DMF**) की गतिविधियों को दर्शाने वाली कॉफी टेबल बुक '**बिल्डिंग ट्रस्ट-ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स**' भी जारी की गई।

- बुक में खनन से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के कल्याण, विकास और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की 40 कहानियाँ हैं।

iii.मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मध्य प्रदेश की क्रिटिकल मिनरल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।

- इस कार्यक्रम में औसत बिक्री मूल्य (ASP) मॉड्यूल और खानों की स्टार रेटिंग का शुभारंभ हुआ।

प्रमुख लोगों:

इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (CM) डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि थे, जिसमें कई राज्यों के खान मंत्रियों ने भी भाग लिया।

प्रदर्शनी "बियॉन्ड माइनिंग" के बारे में:

i.सम्मेलन के मौके पर "बियॉन्ड माइनिंग" प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी।
ii.प्रल्हाद जोशी ने **हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड** के स्टॉल का दौरा किया, जिसने अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए 99.99% शुद्धता की 70,000 तांबे की स्ट्रिप्स और 775 तांबे की तार की छड़ें प्रदान की हैं।

- राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में चट्टानों को जोड़ने के लिए पट्टियों और तार की छड़ों दोनों का उपयोग किया गया है।

iii.उन्होंने कर्नाटक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (NIRM) के स्टॉल का भी दौरा किया, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पत्थरों की गुणवत्ता निरीक्षण में शामिल था।

INDEX

RANKING

इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में UP लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर है

इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) प्लेटफॉर्म पर उच्चतम एंट्रीज (1,56,22,514 एंट्रीज) दर्ज करने में उत्तर प्रदेश (**UP**) लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर है।

- 35,04,828 एंट्रीज के साथ मध्य प्रदेश (**MP**) ने दूसरा स्थान हासिल किया और 16,65,107 एंट्रीज के साथ बिहार तीसरे स्थान पर है।

स्थान	राज्य	एंट्रीज
1	उत्तर प्रदेश	1,56,22,514 एंट्रीज
2	मध्य प्रदेश	35,04,828 एंट्रीज
3	बिहार	16,65,107 एंट्रीज

इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS):

i.ICJS सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी की एक पहल है और 2013 में गृह मंत्रालय (MoHA) द्वारा कार्यान्वित की गई।

ii.ICJS को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न स्तंभों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए बनाया गया था।

कार्यरत:

i.ICJS क्रिमिनल रिकॉर्ड के केंद्रीकृत डेटाबेस के रूप में कार्य करता है; ICJS का चरण II 2022-23 से 2025-26 तक विस्तारित है।

- ICJS चरण II **'वन डाटा वन एंट्री'** के सिद्धांत के साथ काम करता है।

ii.यह फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट (FIR), केस नंबर्स, जेल ID, और अदालती मामलों, परीक्षणों, निर्णयों, अभियोजन और फोरेंसिक का विवरण जैसी जानकारी संग्रहीत करता है।

iii.ICJS द्वारा जांच, खोज, केस इतिहास, केस पेंडेंसी और क्रिमिनल की वर्तमान स्थिति से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाती है।

iv.ICJS तस्वीरों, वीडियो, दस्तावेजी साक्ष्य, अदालती मामले के डेटा और अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को भी संरक्षित कर सकता है।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024: भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर; 62 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश देता है

हेनले & पार्टनर्स द्वारा जारी द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट 62 देशों में वीज़ा-मुक्त या आगमन पर वीज़ा प्रदान करके 80वें स्थान पर है। भारत उज्बेकिस्तान के साथ 80वें स्थान पर है।

- इससे पहले 2023 में, भारत 83वें स्थान पर था और 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश प्रदान किया गया था।

- शीर्ष स्थान पर **6 देश: फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन** हैं, जहां नागरिक 194 यात्रा स्थलों तक वीज़ा-मुक्त पहुंच का आनंद ले रहे हैं।

नोट: हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे अधिक यात्रा-अनुकूल पासपोर्टों की रैंकिंग करता है।

मुख्य विचार:

i.जापान और सिंगापुर पिछले पांच वर्षों से लगातार शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं।

ii.फ़िनलैंड, स्वीडन और दक्षिण कोरिया 193 गंतव्यों तक वीज़ा-मुक्त पहुंच प्रदान करते हुए दूसरे स्थान पर हैं।

iii.ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड 192 गंतव्यों तक पहुंच के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

iv.वैश्विक स्तर पर दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट 104वें स्थान पर अफगानिस्तान का है जिसकी पहुंच केवल 28 देशों तक है।

- सीरिया 29 देशों तक पहुंच के साथ 103वें, इराक 31 देशों तक पहुंच के साथ 102वें और पाकिस्तान 34 देशों तक पहुंच के साथ 101वें स्थान पर है।

आधिकारिक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स: 2024 वैश्विक रैंकिंग के लिए यहां क्लिक करें

शीर्ष 3, निचले 3 पासपोर्ट की सूची

शीर्ष 3		
देश	**पद**	**देशों तक पहुंच**
फ़्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन	1	194
फ़िनलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन	2	193
ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड	3	192
भारत की रैंक टाई		
भारत, उज़्बेकिस्तान	80	62
निचले 3		
अफ़ग़ानिस्तान	104	28
सीरिया	103	29
इराक	102	31

प्रमुख बिंदु:

i.भारतीय भूटान, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, बारबाडोस, थाईलैंड, जॉर्डन, मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरीशस और इंडोनेशिया सहित देशों में वीज़ा-मुक्त यात्रा कर सकते हैं।

ii.भारतीयों को कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मालदीव, म्यांमार, तिमोर-लेस्ते, ईरान, बोलीविया, बुरुंडी, केप वर्डे द्वीप समूह, कोमोरो द्वीप समूह, जिबूती, गैबॉन, मेडागास्कर, सेशेल्स, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, सिएरा लियोन, सोमालिया, समोआ, तंजानिया और ज़िम्बाब्वे में आगमन पर वीज़ा मिल सकता है।

पूरी सूची के लिए यहां क्लिक करें

iii.हालाँकि, 164 देशों को भारतीय यात्रियों से वीज़ा की आवश्यकता होती है।

आकलन:

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 199 विभिन्न पासपोर्टों की वीज़ा-मुक्त पहुंच की तुलना 227 यात्रा स्थलों से करता है। रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के डेटा पर आधारित है, और इसका मूल्यांकन कुल गंतव्यों की संख्या के आधार पर किया जाता है जहां इसके धारक वीज़ा-मुक्त यात्रा कर सकते हैं।

हालि के संबंधित समाचार:

i.संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (2023) का 16वां संस्करण प्रकाशित किया। भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर बरकरार है। जबकि स्विट्जरलैंड ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) उसके बाद दूसरे स्थान पर रहे।

ii.ओकला के स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स (अगस्त 2023 संस्करण) के अनुसार, भारत 50.21 Mbps (मेगाबिट प्रति सेकंड) की औसत डाउनलोड गति के साथ 145 देशों में 47वें स्थान पर है। भारत 72 पायदान ऊपर चढ़कर 2022 में 119वें स्थान से 2023 में 47वें स्थान पर पहुंच गया है।

हेनले & पार्टनर्स के बारे में:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी– डॉ. जुएर्ग स्टीफ़न

मुख्यालय– लंदन, यूनाइटेड किंगडम (UK)

स्थापना- 1997

MSCI EM इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पर रहा; चीन सबसे ऊपर है

भारत ने MSCI इमर्जिंग मार्केट्स (EM) इंडेक्स में ताइवान को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान चीन ने हासिल किया है।

- MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत की हिस्सेदारी आठ वर्षों में 7% से बढ़कर **17.1%** हो गई है और 2024 की शुरुआत तक इसके 20% तक बढ़ने का अनुमान है।
- भारत में पिछले 11 वर्षों में सबसे अधिक निवेश देखा गया।
- यह भारत को उभरते बाजारों में एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाता है।

प्रमुख बिंदु:

i.2020 में मानकीकृत विदेशी स्वामित्व सीमा (FOL) और मिडकैप इक्विटी में मजबूत प्रदर्शन के बीच MSCI EM में भारत का प्रतिनिधित्व अक्टूबर 2020 में 8% से दोगुना होकर 17.1% हो गया।

ii.2023 में, 17 नए भारतीय शेयरों को शामिल करने के बाद MSCI स्टैण्डर्ड इंडेक्स में भारत की स्टॉक संख्या बढ़कर **131** हो गई।

iii.घरेलू संस्थागत निवेशकों से लगातार प्रवाह और 2024 की शुरुआत तक MSCI EM इंडेक्स में भारत का भार 20% से अधिक होने की संभावना।

iv.MSCI EM इंडेक्स (8 जनवरी 24) में शीर्ष 5 देश - चीन (26.6), भारत (17.1), ताइवान (15.8), दक्षिण कोरिया (12.6), और ब्राजील (5.7) है।

MSCI EM इंडेक्स के बारे में:

- 1988 में, MSCI इंक, पूर्व में मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल ने MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स लॉन्च किया था जो इस क्षेत्र में पहले निवेश योग्य बेंचमार्क इंडेक्स वैश्विक इक्विटी बाजारों में से एक है। यह 24 EM देशों में बड़े और मध्य कैप प्रतिनिधित्व पर कब्जा करता है। 1,441 घटकों के साथ, इंडेक्स प्रत्येक देश में मुक्त फ्लोट-समायोजित मार्केट पूंजीकरण का लगभग 85% कवर करता है।
- यह इंडेक्स शेयरों का एक संग्रह है जो तेजी से बढ़ते देशों में कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।

स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में गुजरात, केरल, कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टेट्स हैं; नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2023 की घोषणा

8वें नेशनल स्टार्टअप डे 2024 (16 जनवरी, 2024) के अवसर पर, 'स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022- ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज' & चौथे 'नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स (NSA) 2023- सेलेब्रेटिंग अचीवर्स अहेड ऑफ द कर्व' नई दिल्ली, दिल्ली में भारत मंडपम में एक कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप इंडिया, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoCI) की घोषणा की गई।

- विजेताओं को **केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल**, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoCI) द्वारा सम्मानित किया गया।
- स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में, **गुजरात, कर्नाटक, केरल** और **तमिलनाडु** (TN) उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए श्रेणी A (1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या) में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टेट के रूप में उभरे हैं, जबकि **हिमाचल प्रदेश** श्रेणी B (1 करोड़ से कम जनसंख्या) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है।

स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022:

आकलन:

i.इस रैंकिंग अभ्यास में, 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज (UT) का मूल्यांकन पांच प्रदर्शन श्रेणियों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, नेता, महत्वाकांक्षी नेता और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में किया गया।

ii.उनके अनुपालन और प्रगति को देखते हुए मूल्यांकन अवधि 1 अगस्त, 2021 से 31 दिसंबर, 2022 तक थी।

iii.मूल्यांकन 25 कार्य बिंदुओं के साथ 7 सुधार क्षेत्रों पर केंद्रित है, जो फीडबैक सहित अधिकतम 100 अंकों का योगदान देता है।

- सुधार के क्षेत्र इंस्टीटूशनल सपोर्ट, नवाचार & उद्यमिता को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच, इनक्यूबेशन & मेंटरशिप सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, सक्षम लोगों की क्षमता निर्माण, एक सतत भविष्य के लिए रोडमैप हैं।

iv.स्टेट्स को स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने की पहल के आधार पर रैंकिंग दी गई, जिसे जनसंख्या के आकार यानी श्रेणी A & B के आधार पर वर्गीकृत किया गया।

मुख्य विशेषताएं:

रैंकिंग की निम्नलिखित श्रेणी A और श्रेणी B में 5 सर्वश्रेष्ठ कलाकार, 7 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, 8 नेता, 4 महत्वाकांक्षी नेता और 9 उभरते इकोसिस्टम्स हैं:

श्रेणी A

i.महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना को शीर्ष प्रदर्शन करने वालों का नाम दिया गया।

ii.आंध्र प्रदेश (AP), असम, मध्य प्रदेश (MP), उत्तर प्रदेश (UP), और उत्तराखंड को नेता नामित किया गया।

iii.बिहार और हरियाणा को महत्वाकांक्षी नेताओं के रूप में नामित किया गया था।

iv.छत्तीसगढ़, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर (J&K) को उभरते इकोसिस्टम्स के रूप में नामित किया गया है।

श्रेणी B

i.अरुणाचल प्रदेश (AR) और मेघालय इस श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले थे।

ii.गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा को नेता की सूची में रखा गया।

iii.अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और नागालैंड को महत्वाकांक्षी नेताओं के रूप में नामित किया गया था।

iv.चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी और सिक्किम को उभरते इकोसिस्टम्स के रूप में नामित किया गया है।

स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 परिणामों की सूची:

वर्ग	श्रेणी A	श्रेणी B
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले	गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु (TN)	हिमाचल प्रदेश (HP)
शीर्ष प्रदर्शक	महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना	अरुणाचल प्रदेश (AR) और मेघालय
नेता	आंध्र प्रदेश (AP), असम, मध्य प्रदेश (MP), उत्तर प्रदेश (UP), और उत्तराखंड	गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा
महत्वाकांक्षी नेता	बिहार और हरियाणा	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और नागालैंड
उभरते इकोसिस्टम्स	छत्तीसगढ़, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर (J&K)	चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी और सिक्किम

स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में:

फरवरी 2018 में लॉन्च की गई स्टार्टअप रैंकिंग का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र का आकलन करना और इसकी वृद्धि और विकास में तेजी लाना है। इस पहल ने स्टेट्स/UT को समर्पित स्टार्टअप नीतियां विकसित करने के लिए प्रेरित किया है, और इसकी वार्षिक रैंकिंग इन नीतियों के विकास और स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के निर्माण में समग्र प्रयासों को ट्रैक करती है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के बारे में:

इसे भारत के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी, 2016 को भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम्स बनाने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल के रूप में लॉन्च किया गया था।

- इसका प्रबंधन एक समर्पित स्टार्टअप इंडिया टीम द्वारा किया जाता है, जो DPIIT को रिपोर्ट करती है।
- अब तक, 117,000 से अधिक स्टार्टअप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। सभी मान्यता प्राप्त व्यक्ति कुछ कर प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं।

नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2023

कार्यक्रम के दौरान, NSA 2023 का चौथा संस्करण भी आयोजित किया गया जो उत्कृष्ट स्टार्टअप्स को पहचानता है, पुरस्कृत करता है, बढ़ावा देता है और विशेष सहायता प्रदान करता है। NSA 2023 प्रतियोगिता के 84 फाइनलिस्टों में से 16 श्रेणियों में 21 विजेताओं को मान्यता देता है।

- जीतने वाले स्टार्टअप को **10 लाख रुपये** मिलेंगे।
- NSA को 2020 में DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया था।

NSA 2023 विजेताओं की सूची:

वर्ग	विजेता स्टार्टअप	शहर / स्टेट	संस्थापक	संक्षिप्त
एयरोइनोवेट अवार्ड	एक्सियल एयरो प्राइवेट लिमिटेड	मेडक, तेलंगाना	बाला प्रवीण कुमार, रमेश कृष्णन	यह रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्नत नियंत्रण प्रणाली, प्रणोदन प्रणाली, सिमुलेशन तकनीक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक विमान समाधान प्रदान करता है।
चैंपियंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज	कंट्री क्ले (OPC) प्राइवेट लिमिटेड	दिल्ली	राशि आकार, सिद्धांत अग्रवाल	यह भारत के विभिन्न राज्यों से लक्जरी कुकरी, डिनरवेयर, बाथवेयर और सजावटी उत्पाद पेश करता है।
एक्सीलेंस इन लोकल टू ग्लोबल	ब्लैकफ्रॉग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	उडुपी, कर्नाटक	मयूर शेट्टी, डोनसन D सूजा	इसने एम्वोलियो नामक एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है, जो इंसुलिन, रक्त सीरम, टीकाकरण और अन्य जैविक सहित नियंत्रित चिकित्सा आपूर्ति की सुरक्षित अंतिम-मील डिलीवरी के लिए अद्वितीय तेज़ शीतलन विधि से सुसज्जित है।
जेनेसिस इनोवेटर ऑफ द ईयर	अत्सुया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	चेन्नई, तमिलनाडु	राहुल गणपति, श्रीदर स्वामी	यह AI, डीप टेक और IoT का उपयोग करके व्यवसायों को उनके स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।
इम्पैक्ट इन रूरल एरियाज	SNL इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड	जयपुर, राजस्थान	सुधांशु गुप्ता, डॉ. लिजा मित्तल	यह इनोफार्म्स अन्य उत्पादों को बनाने के लिए अतिरिक्त पके फलों को गूदे में बदलने के लिए सुविधानुसार एक मिनी एसेप्टिक फल प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करने की अनुमति देता है।
	औमसैट टेक्नोलॉजीज	मुंबई, महाराष्ट्र	रिद्धीश सोनी	इसकी हाइड्रोलाइटिक सेवाएं सार्वजनिक उपयोगिताओं और सिंचाई विभागों को क्षेत्र में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना जल संचरण नेटवर्क में पानी के रिसाव, टूटने और फैलने का सटीक पता लगाने, विश्लेषण करने और पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देती हैं।